घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 205- बुधवार 27 - मई 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.-CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्र. 13/Surguja DN/ 2026-2028

दिल्ली क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज का मुद्दा उठाया

जयशंकर बोले...भारत-यूएस समझौते का मकसद खनिजों की सप्लाई चेन मजबूत करना

नई दिल्ली,26 मई 2026। देश की राजधानी दिल्ली में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक खत्म हो गई है। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने होर्मुज का मुद्दा उठाया। विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा, 'ईरान की तरफ से होर्मुज स्ट्रेट बंद किए जाने का असर अब तेल और ऊर्जा सप्लाई पर दिखने लगा है। क्वाड देशों का कहना है कि समुद्री रास्ते खुले रहना जरूरी हैं और वहां से गुजरने वाले जहाजों पर किसी तरह का टोल या रोक नहीं लगनी चाहिए।' इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री शामिल हुए। अमेरिका की ओर से मार्को रूबियो, जापान से तोशिमित्सु मोतेगी और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से पेनी वोंग मौजूद रहे। विदेश मंत्री जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर कहा कि इसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। जिन देशों पर आतंकी हमले होते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा का अधिकार है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए एक नया बाईलेट्रल फ्रेमवर्क तैयार किया है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर क्वाड बैठक में भी चर्चा हुई और यह आज के समय की बहुत जरूरी पहल है। इस समझौते के तहत दोनों देश खनन, प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और निवेश जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करेंगे। जयशंकर ने कहा कि इसका मकसद महत्वपूर्ण खनिजों की मजबूत और डाईवर्स सप्लाई चेन तैयार करना है, ताकि किसी एक सोर्स पर निर्भरता कम हो सके।

क्वाड के 3 बड़े फैसलों पर सहमति

1. क्वाड देशों ने समुद्र से जुड़ी जानकारी साझा करने और निगरानी बढ़ाने पर सहमति जताई है। बंदरगाहों से जुड़ी सुविधाओं के लिए एक एक्सपर्ट टीम बनाने पर भी विचार होगा। साथ ही फिजी में नया पोर्ट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा और समुद्र के नीचे बिछी इंटरनेट केबल्स पर मिलकर काम होगा।
2. क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक साझा फ्रेमवर्क तैयार किया है। भारत और अमेरिका ने भी इस मुद्दे पर अलग समझौता किया है। क्वाड अब इस काम में दूसरे देशों को भी जोड़ने की कोशिश करेगा।
3. इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखने के लिए नई पहल शुरू की गई है। इसमें नई तकनीक,बेहतर प्रबंधन,नीतियां,अंतरराष्ट्रीय बाजार की जानकारी और इमरजेंसी अभ्यास जैसी चीजें शामिल होंगी।

क्वाड बैठक में 5 बड़े ऐलान...

- क्वाड देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क शुरू करने का फैसला किया,जिसके तहत खनन,प्रोसेसिंग, रीसाइक्लिंग और सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए मिलकर निवेश और सहयोग बढ़ाया जाएगा।
- भारत और अमेरिका ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ सप्लाई सुरक्षित करने के लिए द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए,जिससे दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक सहयोग बढ़ेगा।
- क्वाड देशों ने इंडो-पैसिफिक में ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने के लिए नई पहल शुरू की है,जिसके तहत फ्यूल सिक्योरिटी फोरम और क्षेत्रीय ऊर्जा सहयोग को आगे बढ़ाया जाएगा।
- हिंद महासागर और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री निगरानी बढ़ाने के लिए क्वाड देश सैटेलाइट डेटा साझा करेंगे,जिससे तस्करी,अवैध मछली पकड़ने और आपदा राहत में मदद मिलेगी।
- क्वाड देशों ने फिजी में 'पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर' परियोजना शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत बंदरगाह इंफ्रास्ट्रक्चर और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत किया जाएगा।

यह समझौता रणनीतिक साझेदारी का बड़ा उदाहरण : मार्को रूबियो

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच हुआ क्रिटिकल मिनरल्स समझौता दोनों देशों की मजबूत रणनीतिक साझेदारी का बड़ा उदाहरण है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत दोनों चाहते हैं कि महत्वपूर्ण खनिजों और सप्लाई चेन तक लंबे समय तक भरोसेमंद पहुंच बनी रहे,क्योंकि ये नई तकनीक और आधुनिक उद्योगों के लिए बेहद जरूरी हैं। रूबियो ने कहा कि फरवरी में वॉशिंगटन में हुए क्रिटिकल मिनरल्स फोरम से इस सहयोग की शुरुआत हुई थी और अब यह समझौते तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका नहीं चाहते कि महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई किसी एक देश या एक स्रोत के नियंत्रण में रहे, क्योंकि इससे भविष्य में दबाव या संकट पैदा हो सकता है।

जापान बोला- इंडो-पैसिफिक में ताकत बढ़ाएगा क्वाड

क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के बाद जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने कहा कि फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक को मजबूत करने में क्वाड की भूमिका लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि इंडो-पैसिफिक देशों को इतना मजबूत बनाना जरूरी है कि वे अपना भविष्य खुद तय कर सकें। चारों देशों ने साफ किया है कि वे ताकत या दबाव के जरिए हालात बदलने की कोशिशों का विरोध करते हैं। इसके अलावा जापानी विदेश मंत्री ने बताया कि जरूरी खनिजों (क्रिटिकल मिनरल्स) के निर्यात पर लग रही पाबंदियों को लेकर भी चिंता जताई गई। सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए क्वाड ने नया क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क शुरू किया है।

भारत-अमेरिका के बीच क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता

विदेश मंत्री एस. जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ की सप्लाई सुरक्षित करने के लिए भारत-अमेरिका के बीच एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए।

कर्नाटक सीएम बदलने की खबरें केवल अटकलें : वेणुगोपाल

बैठक में राज्यसभा-एमएलसी चुनाव पर चर्चा हुई, सिद्धारमैया-शिवकुमार राहुल-खड़गे से मिले

नई दिल्ली,26 मई 2026। कर्नाटक के सीएम बदलने की अटकलों के बीच मंगलवार को राज्य के सीएम सिद्धारमैया और डीप्टी सीएम डीके शिवकुमार की दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी संग बैठक हुई। बैठक के बाद पार्टी के संगठन महासचिव और लोकसभा सांसद वेणुगोपाल ने कहा- जो अटकलें लगाई जा रही हैं, वे सिर्फ अटकलें हैं, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बैठक में राज्यसभा और विधान परिषद चुनावों पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री पद या नेतृत्व परिवर्तन को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है। कर्नाटक की राज्यसभा और विधान परिषद सीटों के उम्मीदवारों के नाम अन्य राज्यों की सीटों के साथ घोषित किए जाएंगे। हालांकि, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धारमैया को सीएम पद छोड़ने का कहा है। उन्हें राज्यसभा जाने

का ऑफर दिया है, लेकिन सिद्धारमैया ने सीएम पद छोड़ने से इनकार किया है।

शिवकुमार ने कहा था- दिल्ली जाना जरूरी होता है : कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और डीप्टी सीएम डीके शिवकुमार सोमवार रात को दिल्ली पहुंचे थे। सिद्धारमैया के साथ कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर आए थे। दिल्ली पहुंचने के बाद सिद्धारमैया ने कहा- हाईकमान ने बुलाया है,इसलिए आया हूं। बैठक का एजेंडा क्या है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। वेणुगोपाल ने फोन कर समय और तारीख बताई थी। वहीं शिवकुमार ने दिल्ली रवाना होने से पहले कहा था-कुछ परिस्थितियों में दिल्ली जाना जरूरी हो जाता है, इसलिए जा रहा हूं। वहीं, कर्नाटक सरकार में मंत्री सतीश जारकीहोली ने कहा था कि दिल्ली में होने वाली बैठक का मकसद पार्टी के अंदर चल रहे मुद्दों को सुलझाना है। कांग्रेस कार्यकर्ता गृह मंत्री जी परमेश्वर के समर्थन में भी आवाज उठा रहे हैं। इससे पार्टी के अंदर शक्ति संतुलन की चर्चा और तेज हो गई है। इससे पहले सोमवार को जब खड़गे से कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा- मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल जी बोलेंगे। खड़गे के इसी बयान को लेकर भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष केवल नाम के अध्यक्ष हैं और पार्टी रिमोट कंट्रोल से चल रही है। इतने बड़े मुद्दे पर खड़गे कह रहे हैं कि राहुल गांधी जवाब देंगे। इससे साफ है कि असली ताकत किसके पास है। पूनावाला ने कांग्रेस पर आंतरिक कलह का आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी में केरल, हिमाचल और अब कर्नाटक में भी सत्ता संघर्ष चल रहा है। उन्होंने कहा- कांग्रेस को जनता से ज्यादा कुर्सी की चिंता है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। शिवकुमार के समर्थक विधायकों का कहना है कि 2023 में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5-2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन सिद्धारमैया समर्थक इसे नकारते आए हैं।

जनसांख्यिकीय बदलाव पर केंद्र सरकार ने बनाई उच्चस्तरीय समिति : शाह

नई दिल्ली,26 मई 2026। केंद्र सरकार ने असामान्य जनसंख्यिकी बदलाव और अवैध घुसपैठ के अध्ययन के लिए उच्चस्तरीय समिति गठित की है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रकाश प्रभाकर नावलेकर की अध्यक्षता वाली समिति राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक प्रभावों का आकलन करेगी।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए कहा कि घुसपैठ और अन्य कारणों से होने वाला असामान्य जनसांख्यिकीय बदलाव देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने 'हाई-लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज' का गठन कर दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इस उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा की थी।

उन्नाव में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा

दरोगा समेत 7 की मौत,24 यात्री घायल,सीएम योगी ने जताया शोक

उन्नाव,26 मई 2026। उन्नाव जिले में दिल्ली से गोरखपुर जा रही प्राइवेट स्लीपर बस मंगलवार सुबह पांच बजे लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक दरोगा समेत सात यात्रियों की मौत हो गई। वहीं, तीन पुलिसकर्मी समेत 24 यात्री घायल हुए हैं। हादसे के वक्त बस में 52 यात्री थे। बस की रफ्तार इतनी तेज थी कि पलटने के बाद100 मीटर तक घिसती चली गई। दिल्ली से गोरखपुर जा रही स्लीपर बस में कुल 52 यात्री सवार थे। तेज रफ्तार होने के कारण चालक नियंत्रण खो बैठा और बस पुलिया से टकराने के बाद पलट गई। हादसे के बाद यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। करीब आधे घंटे बाद यूपीडा कर्मी और पुलिस मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया।

24 घायल लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर : घायलों को एंबुलेंस से सीएचसी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद 24 घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। एसपी जयप्रकाश सिंह ने बताया कि कुछ घयल यात्रियों की हालत गंभीर होने से लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है।

सीएम ने जताया शोक

लखनऊ-आगरा एक्सप्रेसवे पर हुए भीषण सड़क हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया है। उन्होंने हादसे में हुई मौतों पर गहरा शोक व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अधिकारियों को दुर्घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, प्रशासन को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए कहा है। कहा कि मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा।

वॉट्एसेप का बड़ा अपडेट..अब बिना फोन नंबर शेयर किए कर सकेंगे चैटिंग प्राइवेसी की नहीं होगी कोई टेंशन

नई दिल्ली,26 मई 2026। वॉट्सऐप पर अब तक किसी से भी बातचीत करने के लिए मोबाइल नंबर शेयर करना बेहद जरूरी होता था, लेकिन अब कंपनी अपने यूजर्स को एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। बहुत जल्द

वॉट्सऐप पर एक ऐसा फीचर आने वाला है, जिससे आप बिना अपना नंबर किसी को दिए आराम से चैटिंग कर सकेंगे। अभी तक यह सुविधा मुख्य रूप से इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम पर ही उपलब्ध थी, जहां लोग अपनी पहचान छिपाकर बातें कर सकते थे। लेकिन अब मेटा के स्वामित्व वाला वॉट्सऐप भी अपने करोड़ों यूजर्स की प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए इस नए 'यूजरनेम' फीचर पर तेजी से काम कर रहा है।

कैसे काम करेगा वॉट्सऐप का नया फीचर?

इस नए अपडेट के बाद,वॉट्सऐप यूजर्स इंस्टाग्राम या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की तरह ही अपना एक खास और अनोखा यूजरनेम बना सकेंगे। इस फीचर के आने से उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा होगा जो अपनी निजता (प्राइवेसी) को लेकर हमेशा सतर्क रहते हैं। अक्सर लोग ऑनलाइन ग्रुप्स, बिजनेस डील्स या नए अनजान लोगों से अपना पर्सनल नंबर साझा करने से कतराते हैं। ऐसे में यह यूजरनेम फीचर उनके लिए एक सुरक्षित ढाल का काम करेगा। आप किसी को भी सिर्फ अपना यूजरनेम दे सकेंगे और चैटिंग के दौरान सामने वाले व्यक्ति को आपका फोन नंबर दिखाई ही नहीं देगा, जिससे आपकी असली पहचान पूरी तरह सुरक्षित रहेगी।

फर्जी अकाउंट्स और धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

हर नए फीचर के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं,जैसे फर्जी प्रोफाइल बनाकर किसी को धोखा देना या किसी और की पहचान का इस्तेमाल करना। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, वॉट्सऐप इस खतरे से निपटने के लिए सख्त नियम भी तैयार कर रहा है। हर यूजर का यूजरनेम एक-दूसरे से बिल्कुल अलग होगा और कुछ विशेष शब्दों या फॉर्मेट के इस्तेमाल पर कंपनी की तरफ से रोक भी लगाई जा सकती है, ताकि धोखाधड़ी को जड़ से खत्म किया जा सके। इसके अलावा, यदि कोई यूजर अपना यूजरनेम बदलता है, तो इसकी सूचना भी सामने वाले व्यक्ति को मिल जाएगी।

सीएम सुवेंदु का बड़ा ऐलान...पश्चिम बंगाल में 5 रुपये में मिलेगा मछली-भात,स्कूल-धार्मिक स्थलों के पास नहीं खुलेंगी शराब दुकानें

महिलाओं को प्रति माह 3,000

कोलकाता,26 मई2026। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कई अहम फैसलों को मंजूरी दी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 27 मई से अन्नपूर्णा योजना के लिए फॉर्म जारी करना शुरू कर देगी, जिसके तहत महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि स्कूलों,कॉलेजों और पूजा स्थलों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही आम लोगों के लिए भोजन को लेकर भी अहम घोषणा की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सप्ताह में 2 बार 5 रुपये में मछली और चावल का भोजन उपलब्ध

कराएगी। उनके अनुसार,लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस पहल के तहत लगभग 400 विशेष कैंटीन स्थापित की जाएंगी। बंगाल की खाद्य संस्कृति में मछली-भात बेहद अहम माना जाता है और सरकार इसे कम कीमत पर उपलब्ध कराकर गरीब तबकों को राहत देना चाहती है। चुनावों के दौरान भी ये मुद्दा उठा था। मुख्यमंत्री सुवेंदु ने कहा, स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि युवा शराब के लालच में न पड़ें। अन्नपूर्णा योजना के फॉर्म कल से राज्य सचिवालय द्वारा जारी किए जाएंगे। इस योजना के तहत सभी भारतीय लाभ प्राप्त करने के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य विभाग से अलग होकर एक आयुष विभाग भी स्थापित करेगी।

राम रहीम को फिर मिली 30 दिन की पैरोल,20 साल की सजा में 16वीं बार आया बाहर

रोहतक,26 मई 2026। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह एक बार फिर जेल से बाहर आ गया है। हरियाणा सरकार ने गुरमीत राम रहीम को 30 दिन की पैरोल मंजूर की है। इसके बाद मंगलवार सुबह वह रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकला। जानकारी के अनुसार, गुरमीत राम रहीम सुबह करीब 6 बजकर 34 मिनट पर जेल से बाहर आया। इस दौरान जेल परिसर के बाहर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं थी। गौरतलब है कि साध्वियों के यौन शोषण और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड के मामले में 20 साल की सजा काट रहा गुरमीत राम रहीम अगस्त 2017 से सुनारिया जेल में बंद है।

मध्य प्रदेश के पन्ना में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंसी,5 मजदूरों की मौत

पन्ना,26 मई 2026। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में मंगलवार को कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी धंस गई, जिसमें दबकर 5 मजदूरों की मौत हुई है। हादसा अजयगढ़ तहसील में आने वाले बीहरपुरवा गांव में हुआ है। मौके पर कई मजदूर काम कर रहे थे, तभी यह हादसा हुआ। अभी तक 3 मजदूरों के शव निकाले गए हैं, जबकि 2 की खोज चल रही है। घटना की खबर से पूरे गांव में हड़कंप मच गया है। जिला कलेक्टर पन्ना ने बताया कि मनरेगा योजना के तहत सार्वजनिक सिंचाई कूप के लिए कुएं का निर्माण किया जा रहा था। यह काम पिछले 10 दिनों से चल रहा था। मंगलवार सुबह अचानक

मिट्टी धंस गई,तभी वहां काम कर रहे 5 मजदूर मिट्टी में दब गए। घटना के समय 2 अन्य मजदूर कुएं से बाहर थे, जिससे वे बच गए। मृतकों में 3 मजदूर एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। ग्रामीणों और मृतकों के परिजनों का कहना है कि कुएं की खुदाई के दौरान सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई है, जिससे यह हादसा हुआ है। मौके पर स्थानीय प्रशासन, पुलिस और बचाव दल की टीम पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य चल रहा है। मिट्टी को हटाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। कुएं का निर्माण कौन करवा रहा था, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है।

प्रधानमंत्री व केंद्रीय गृहमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर फिर कानूनी पचड़े में फंसे राहुल गांधी,परिवाद पर 16 को होगी सुनवाई

नई दिल्ली,26 मई 2026। लोकसभा में विपक्ष के नेता व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को लेकर विवादित टिप्पणी को लेकर फिर न्यायिक प्रक्रिया में फंस गए हैं। एक मुस्लिम भाजपा नेता ने रायबरेली कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया है। कोर्ट ने परिवाद को दर्ज कर लिया और अगली सुनवाई की तिथि कोर्ट ने 16 जून को नियत की है। शकील अहमद खान ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रतिशोध की भावना से देश के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृहमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, इससे उन्हें गहरा आघात पहुंचा है और उनकी मानहानि हुई है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने देश का माहौल खराब करने के लिए सार्वजनिक मंच से टिप्पणी कर प्रधानमंत्री,

गृहमंत्री और भाजपा की छवि खराब की गई है। शकील अहमद खान ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस स्तर से कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद उन्होंने एमपी-एमएलए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट ने मामले को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए 16 जून की तारीख तय की है। उल्लेखनीय है कि सोमवार को जिले के न्यायालय पंचम अपर सिविल जज (जूनियर डिवीजन) विनयशील की कोर्ट में भाजपा नेता शकील अहमद खान ने मानहानि का परिवाद दर्ज कराया है।

ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी सांसद देबाशीष सामंतराय भाजपा में शामिल

नई दिल्ली,26 मई 2026। ओडिशा की सत्ता से बाहर हुई बीजू जनता दल राजनीतिक संकट से गुजर रही है। मंगलवार को पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के करीबी राज्यसभा सांसद देबाशीष सामंतराय बीजेडी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। उनको दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओडिशा भाजपा अध्यक्ष मनमोहन सामल की मौजूदगी में पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। सामंतराय ने सोमवार को पटनायक को पत्र भेजकर पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया था। भाजपा में शामिल होने से पहले सामंतराय ने सोमवार को राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन से मिलकर उनको अपना इस्तीफा सौंपा था। सामंतराय ने सोमवार को पटनायक को लिखे त्यागपत्र में कहा था कि उन्होंने पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास के साथ खुद को पार्टी के हितों के लिए समर्पित रखा, लेकिन कुछ समय से एहसास हुआ कि उन्हें साजिश के तहत छोटा दिखाया जा रहा है।

संपादकीय

विकसित भारत के निर्माण की राह

जब मैं तिरुप्पुर के स्कूल में पढ़ता था,तब मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठते थे कि भारत अपनी महानता कब वापस पाएगा? हमारे गरीब और वंचित भाई-बहनों को सम्मानजनक जीवन कब मिलेगा? मुझे खुशी है कि किशोरावस्था में मेरे मन में जो विचार थे,वे अब साकार हो रहे हैं। मैं अक्सर खुद को स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों की याद दिलाता था,उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको। स्वामीजी के ये उद्गार हर व्यक्ति में देशभक्ति और समर्पण की भावना जगाने की अपार शक्ति रखते हैं।

मेरा हमेशा यह विश्वास रहा कि जब भारत अपनी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ेगा, तब वह पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने वाला राष्ट्र बनकर उभरेगा। अब हमें अपनी आंखों के सामने तिरुवल्लुवर के इन शब्दों की सच्चाई देखने का अवसर मिल रहा है-जो अपने संकल्प में अडिग रहते हैं,वे ठीक वही हासिल करते हैं,जिसकी उन्होंने कल्पना की होती है। पिछले एक दशक में मुझे यह देखकर खुशी होती है कि हमारा देश जबरदस्त ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।आज जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी और अनिश्चितताओं से जूझ रही है, तब भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से आगे बढ़ रही है। इस दौर को निरंतर विकास का युग बनाने के लिए सरकार और जनता दोनों का साझा उत्साह ही इस प्रगति का कारण है। एक समय कमजोर अर्थव्यवस्था माने जाने वाला हमारा देश आज चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और जल्द ही तीसरी बड़ी आर्थिकी बनने की दिशा में अग्रसर है। हमारा आर्थिक विकास समावेशी रहा है।पिछले एक दशक में लगभग 25 करोड़ भारतवासी अत्यधिक गरीबी से बाहर निकलकर सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सक्षम हुए हैं। अब तक भारत में गरीब और बेघर लोगों के लिए लगभग चार करोड़ पक्के घर बनाए जा चुके हैं। 12 करोड़ से अधिक लोगों को पाइप से पीने के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है, जिस पर 2.3 लाख करोड़ रुपये का खर्च किया जा रहा है। मैंने गांवों में लोगों को इलाज की सुविधा न मिलने के कारण परेशान होते देखा है। उनके परिवारों की पीड़ा देखकर मुझे दुःख होता था।

आज देश इस संकल्प के साथ आयुष्मान भारत योजना चला रहा है कि स्वास्थ्य सेवाएं हर व्यक्ति तक पहुंचें। इसी का परिणाम है कि अब 44 करोड़ से अधिक लोगों को पीएम आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिल रहा है। केवल पिछले एक वर्ष में ही 2.5 करोड़ लोगों ने इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज प्राप्त किया है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत अब तक चार लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जा चुकी है। तीन करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी और नमो ड्रोन दीदी बनकर अपना जीवन संवार चुकी हैं। महिलाओं के दैनिक जीवन को आसान बनाने और उनके स्वास्थ्य की चिंता करते हुए लगभग दो करोड़ नए एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद और राज्य विधानसभाओं में आधी आबादी की भागीदारी को और सशक्त बनाएगा।

प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं तथा एकलव्य माडल आवासीय विद्यालयों ने क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को बहुत लाभ पहुंचाया है। युवा शक्ति के लिए पिछले दस वर्षों में ही 13 नए आइआइटी स्थापित किए गए हैं। आइआइएम की संख्या 13 से बढ़कर 21 हो गई है। एम्स की संख्या सात से बढ़कर 23 हो चुकी है। मेडिकल कालेजों की संख्या भी बढ़कर 823 हो गई है। यह गर्व की बात है कि मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या 51,348 से बढ़कर 1,29,603 हो गई है। हम विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे का लगभग 99 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है। वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। हवाई अड्डों की संख्या भी 74 से बढ़कर 163 हो गई है और उड़ान योजना के तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सुलभ हुई है। नए पंबन ब्रिज से लेकर चिनाब ब्रिज हो या बोगीबील पुल, भारत अब आधुनिक बुनियादी ढांचे के नए आयाम स्थापित कर रहा है। जो सीमावर्ती गांव कभी भारत के अंतिम गांव माने जाते थे, वे अब देश के प्रथम गांव बन चुके हैं और वाइब्रेंट विलेज स्कीम के माध्यम से उनका विकास किया जा रहा है।

दोबारा लौट रहे लोग लकड़ी की खाट पर

आधुनिक जीवनशैली के बीच परंपरा,स्वास्थ्य और पर्यावरण का पुनर्जागरण

सत्यवान सौरभ
भिवानी,हरियाणा

एक समय था जब भारतीय घरों,आँगनों,चौपालों और खेतों में लकड़ी की खाट जीवन का अभिन्न हिस्सा हुआ करती थी। सुबह की चाय से लेकर रात की नींद तक,खाट केवल एक फर्नीचर नहीं बल्कि सामाजिक,सांस्कृतिक और पारिवारिक जीवन का केंद्र थी। लेकिन जैसे-जैसे आधुनिकता का प्रभाव बढ़ा, शहरीकरण ने गति पकड़ी और बाजार में नए-नए प्रकार के बेड, सोफा-कम-बेड तथा महंगे गद्दे आने लगे,खाट धीरे-धीरे घरों से गायब होने लगी। इसे पुरातन,ग्रामीण और पिछड़ेपन का प्रतीक मान लिया गया। परंतु समय का चक्र एक बार फिर घूम रहा है। आज लोग दोबारा लकड़ी की खाट की ओर लौट रहे हैं। यह वापसी केवल एक पारंपरिक वस्तु की वापसी नहीं है,बल्कि जीवन के प्रति बदलती सोच, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और प्रकृति के साथ संतुलन की तलाश का प्रतीक भी है।
भारतीय समाज में खाट का इतिहास बहुत पुराना है। इसे चारपाई,मंजी या खटिया जैसे नामों से भी जाना जाता है। लकड़ी के मजबूत ढाँचे और रस्सियों या पट्टियों से बुनी हुई यह संरचना सदियों तक भारतीय जीवन का आधार रही। गाँवों में चौपाल की पहचान खाटों से होती थी। परिवार के बुजुर्ग खाट पर बैठकर निर्णय लेते थे,किसान दिनभर के श्रम के बाद खाट पर विश्राम करते थे और बच्चे उसी पर खेलते-कूदते बड़े होते थे। यह केवल आराम का साधन नहीं थी बल्कि सामाजिक संवाद का मंच भी थी। आज भी ग्रामीण भारत में खाट पर बैठकर होने वाली चर्चाएँ लोकतांत्रिक संवाद की सबसे सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति मानी जाती हैं।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

पिछले कुछ दशकों में जीवनशैली में बड़े बदलाव आए। लोगों ने आधुनिक फर्नीचर को प्रगति और समृद्धि का प्रतीक मान लिया। बड़े-बड़े बेड, मोटे गद्दे और आकर्षक डिज़ाइन वाले फर्नीचर घरों की आवश्यकता बन गए। विज्ञापनों ने भी लोगों को यह विश्वास दिलाया कि आराम केवल महंगे गद्दों और आधुनिक बिस्तरों में ही संभव है। परिणामस्वरूप खाट धीरे-धीरे घरों से बाहर होती चली गई। लेकिन अब जब लोग स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, बढ़ते तनाव और कृत्रिम जीवनशैली के दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं, तब वे उन पारंपरिक विकल्पों को नए दृष्टिकोण से देखने लगे हैं जिन्हें कभी उन्होंने स्वयं ही त्याग दिया था।

लकड़ी की खाट की लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण स्वास्थ्य संबंधी लाभ हैं। आधुनिक जीवनशैली में कमर दर्द, गर्दन दर्द और रीढ़ से जुड़ी समस्याएँ तेजी से बढ़ी हैं। बहुत अधिक मुलायम गद्दों पर सोना कई लोगों के लिए असुविधाजनक साबित हुआ है। इसके विपरीत खाट का ढाँचा शरीर को संतुलित सहारा देता है। रस्सियों से बुनी खाट शरीर के भार को समान रूप से वितरित करती है,जिससे रीढ़ पर अनावश्यक दबाव कम पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी अनेक बुजुर्ग वर्षों तक खाट पर सोने के कारण बेहतर शारीरिक स्थिति में दिखाई देते हैं। यद्यपि हर व्यक्ति की स्वास्थ्य आवश्यकताएँ अलग होती हैं, फिर भी खाट को प्राकृतिक और संतुलित विश्राम का साधन माना जाता है।

गर्म जलवायु वाले भारत में खाट की उपयोगिता और भी अधिक है। फोम और स्प्रिंग वाले गद्दे अक्सर शरीर की गर्मी को रोक लेते हैं, जिससे गर्मियों में असुविधा बढ़ जाती है। इसके विपरीत खाट के नीचे और ऊपर दोनों ओर से हवा का प्रवाह बना रहता है। यह प्राकृतिक वेंटिलेशन शरीर को ठंडक प्रदान करता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। बिजली की बढ़ती खपत और एयर कंडीशनर पर निर्भरता के इस दौर में खाट का यह गुण विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो जाता है।

पर्यावरणीय दृष्टि से भी खाट का महत्व बढ़ रहा है। आज दुनिया टिकाऊ विकास और पर्यावरण संरक्षण की बात कर रही है। आधुनिक फर्नीचर उद्योग में प्लास्टिक,सिंथेटिक फोम और रासायनिक पदार्थों का व्यापक उपयोग होता है,जिनका पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके विपरीत लकड़ी और प्राकृतिक रस्सियों से बनी खाट अपेक्षाकृत पर्यावरण-अनुकूल होती है। यह लंबे समय तक चलती है, आसानी से मरम्मत की जा सकती है और इसके अधिकांश हिस्से पुनर्चक्रित या प्राकृतिक रूप से नष्ट हो सकते हैं। ऐसे समय में जब लोग पर्यावरण के प्रति

अधिक संवेदनशील हो रहे हैं, खाट उन्हें एक टिकाऊ विकल्प के रूप में दिखाई देने लगी है।

खाट की वापसी का एक कारण आर्थिक भी है। महंगे फर्नीचर और ब्रांडेड गद्दों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। दूसरी ओर,स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाई गई खाट अपेक्षाकृत सस्ती और टिकाऊ होती है। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में आज भी खाट कम लागत में उपलब्ध है। यह वर्षों तक उपयोग में आ सकती है और आवश्यकता पड़ने पर उसकी रस्सियाँ बदलकर उसे फिर नया बनाया जा सकता है। इस प्रकार खाट केवल सांस्कृतिक विरासत नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी व्यवहारिक विकल्प है।
दिलचस्प बात यह है कि खाट की वापसी केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक सीमित नहीं है। बड़े शहरों में भी लोग इसे नए रूप में अपना रहे हैं। इंटीरियर डिज़ाइनरों ने पारंपरिक खाट को आधुनिक सौंदर्यबोध के साथ प्रस्तुत करना शुरू किया है। आज कई घरों में खाट को बालकनी, गार्डन, टैरेस या लिविंग स्पेस में सजावटी और उपयोगी वस्तु के रूप में रखा जा रहा है। रिसॉर्ट, कैफ़े और होमस्टे भी अपने परिसर में खाट का उपयोग कर रहे हैं ताकि ग्राहकों को देसी और पारंपरिक अनुभव मिल सके। यह दिखाता है कि परंपरा और आधुनिकता का मेल किस प्रकार संभव है।
सोशल मीडिया ने भी खाट की लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज सस्टेनेबल लिविंग, स्लो लाइफ, देसी लाइफस्टाइल और रूट्स की ओर वापसी जैसे विषय युवाओं के बीच लोकप्रिय हो रहे हैं। लोग अपने घरों और फार्महाउसों में खाट के साथ तस्वीरें साझा करते हैं। अनेक युवा,जो कभी खाट को केवल गाँवों की वस्तु मानते थे,अब उसे जीवनशैली और पहचान का हिस्सा समझने लगे हैं। यह परिवर्तन बताता है कि नई पीढ़ी अपनी सांस्कृतिक विरासत को नए नजरिए से देख रही है।

खाट का सांस्कृतिक महत्व भी कम नहीं है। भारतीय साहित्य,लोकगीतों और फिल्मों में खाट का उल्लेख बार-बार मिलता है। यह ग्रामीण जीवन, आत्मीयता और सामूहिकता का प्रतीक रही है। जब परिवार के सदस्य एक साथ खाट पर बैठकर बातचीत करते थे, तब संवाद स्वाभाविक रूप से विकसित होता था। आज डिजिटल युग में जहाँ लोग एक ही घर में रहते हुए भी मोबाइल स्क्रीन में व्यस्त रहते हैं, वहाँ खाट जैसे सामूहिक बैठने के स्थान फिर से सामाजिक निकटता का माध्यम बन सकते हैं।

हालाँकि खाट की वापसी का अर्थ यह नहीं है कि आधुनिक फर्नीचर पूरी तरह अप्रासंगिक हो गया है। आधुनिक जीवन की आवश्यकताएँ अलग हैं और कई परिस्थितियों में आधुनिक बेड अधिक सुविधाजनक भी हो सकते हैं। लेकिन खाट की बढ़ती लोकप्रियता यह संकेत अवश्य देती है कि लोग केवल सुविधा नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, पर्यावरण और सांस्कृतिक जुड़ाव को भी महत्व देने लगे हैं। वे ऐसे विकल्प खोज रहे हैं जो जीवन को अधिक संतुलित और स्वाभाविक बना सकें।

वास्तव में खाट का पुनरागमन उस व्यापक सामाजिक बदलाव का हिस्सा है जिसमें लोग अपनी जड़ों की ओर लौटने का प्रयास कर रहे हैं। चाहे पारंपरिक भोजन हो,जैविक खेती हो, मिट्टी के बर्तन हों या लकड़ी की खाट–लोग अब यह महसूस कर रहे हैं कि विकास का अर्थ केवल नई तकनीक अपनाना नहीं है। विकास का वास्तविक अर्थ उन परंपराओं को भी समझना है जो समय की कसौटी पर खरी उतरी हैं और जिनमें जीवन को सरल, स्वस्थ और संतुलित बनाने की क्षमता है।

आज जब दुनिया तेज़ी से बदल रही है और जीवन पहले से अधिक जटिल होता जा रहा है, तब लकड़ी की खाट हमें सादगी का संदेश देती है। वह याद दिलाती है कि आराम केवल महंगे साधनों से नहीं,बल्कि प्रकृति के अनुकूल जीवनशैली से भी प्राप्त किया जा सकता है। खाट की ओर लौटते कदम इस बात का संकेत हैं कि समाज अपनी सांस्कृतिक स्मृतियों, पारंपरिक ज्ञान और पर्यावरणीय समझ को फिर से महत्व देने लगा है।

संभव है कि आने वाले वर्षों में खाट फिर कभी हर घर का मुख्य फर्नीचर न बने,लेकिन उसका पुनर्जागरण यह अवश्य सिद्ध करता है कि परंपरा कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होती। जब आधुनिक जीवन की चुनौतियाँ बढ़ती हैं,तब समाज अक्सर अपनी जड़ों में समाधान खोजता है। लकड़ी की खाट की वापसी इसी खोज की कहानी है–एक ऐसी कहानी जिसमें स्वास्थ्य है,पर्यावरण है, संस्कृति है और जीवन को अधिक मानवीय बनाने की आकांक्षा भी।

यही कारण है कि आज लोग दोबारा लकड़ी की खाट पर लौट रहे हैं। वे केवल एक पुराने फर्नीचर को नहीं अपना रहे,बल्कि एक ऐसे जीवन-दर्शन को पुनर्जीवित कर रहे हैं जो सादगी, संतुलन,आत्मीयता और प्रकृति के साथ सामंजस्य पर आधारित है। यही इस वापसी का सबसे बड़ा अर्थ और सबसे बड़ी उपलब्धि है।

डीजल-पेट्रोल के बढ़ते भाव से नागरिक हलाकान

डॉ. प्रियंका सौरभ
हिसार, हरियाणा

पिछले कुछ समय से देश के शहरों और गांवों में एक चिंता लगातार सुनाई दे रही है–पेट्रोल और डीज़ल की बढ़ती कीमतें। यह चिंता केवल वाहन चलाने वालों तक सीमित नहीं है,बल्कि इसका प्रभाव हर उस नागरिक पर पड़ता है जो रोजमर्रा की वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है। जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर केवल पेट्रोल पंप तक नहीं रहता; वह परिवहन, खाद्य पदार्थों, निर्माण सामग्री,कृषि लागत और घरेलू बजट तक पहुंच जाता है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि को केवल एक आर्थिक घटना मानना पर्याप्त नहीं है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और नीतिगत प्रश्न भी है, जो सरकार, बाजार और नागरिक–तीनों से जुड़ा हुआ है।

प्रकाशकः दैनिक घटती-घटना

भारत जैसे विकासशील देश में ऊर्जा केवल आर्थिक गतिविधियों का आधार नहीं है,बल्कि सामाजिक गतिशीलता और विकास की भी महत्वपूर्ण शक्ति है। देश का विशाल परिवहन तंत्र,कृषि क्षेत्र,औद्योगिक उत्पादन और सेवा क्षेत्र बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों पर निर्भर हैं। ऐसे में जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं,तो उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था के लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देता है। यही कारण है कि पेट्रोल के बढ़ते भाव हमेशा जनचर्चा और राजनीतिक बहस का विषय बन जाते हैं।

पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना आवश्यक है कि भारत अपनी तेल आवश्यकताओं का अधिकांश हिस्सा आयात करता है। देश अपनी कुल कच्चे तेल की जरूरत का 80 प्रतिशत से अधिक विदेशों से खरीदता है। इसका अर्थ यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में होने वाले उतार-चढ़ाव का सीधा प्रभाव भारतीय उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ता है। यदि वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ती है तो भारत को अधिक भुगतान करना पड़ता है, और उसका असर अंततः खुदरा कीमतों में दिखाई देता है।

वैश्विक तेल बाजार केवल आर्थिक कारकों से प्रभावित नहीं होता। इसके पीछे भू-राजनीतिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पश्चिम एशिया में तनाव,समुद्री मार्गों की सुरक्षा,प्रमुख तेल उत्पादक देशों की उत्पादन नीतियां,रूस-यूक्रेन संघर्ष जैसे कारक तेल की कीमतों को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्रीय संघर्ष या आपूर्ति संकट का असर कुछ ही दिनों में अंतरराष्ट्रीय बाजार पर दिखाई देने लगता है। भारत जैसे आयात-निर्भर देश के लिए यह एक बड़ी चुनौती है क्योंकि घरेलू बाजार को इन परिस्थितियों से पूरी तरह अलग नहीं रखा जा सकता।

हालांकि अंतरराष्ट्रीय बाजार एक महत्वपूर्ण कारण है,लेकिन पेट्रोल की कीमतों का पूरा सच केवल वहीं तक सीमित नहीं है। भारत में पेट्रोल और डीज़ल की खुदरा कीमतों में करों की भी बड़ी भूमिका होती है। पेट्रोल की अंतिम कीमत में कच्चे तेल की लागत के अलावा केंद्र सरकार का उत्पाद शुल्क,राज्य सरकारों का मूल्य वर्धित कर (वैट),परिवहन लागत और डीलर कमीशन भी शामिल होता है। यही कारण है कि अलग-अलग राज्यों में पेट्रोल की कीमतें अलग-अलग होती हैं।

तेल पर लगने वाले कर सरकारों के लिए राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन करों से प्राप्त आय का उपयोग सड़क निर्माण,बुनियादी ढांचे,स्वास्थ्य, शिक्षा और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्तपोषण में किया जाता है। लेकिन दूसरी ओर यही कर आम नागरिकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ भी डालते हैं। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है और कर संरचना में कोई राहत नहीं मिलती,तब उपभोक्ताओं को दोहरी मार झेलनी पड़ती है। यही स्थिति अक्सर राजनीतिक बहस का कारण बनती है।

पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव परिवहन क्षेत्र पर दिखाई देता है। टैक्सी चालक,ऑटो चालक,ट्रक मालिक, बस संचालक और डिलीवरी सेवाओं से जुड़े लाखों लोग बढ़ती लागत

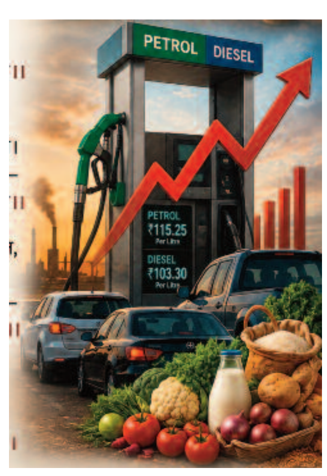

का सामना करते हैं। उनके सामने सामान्यतः दो विकल्प होते हैं–या तो बढ़ी हुई लागत को स्वयं वहन करें अथवा किराए और सेवा शुल्क बढ़ाकर उसका भार उपभोक्ताओं पर डाल दें। अधिकांश मामलों में दूसरा विकल्प अपनाया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ने लगती हैं।

यहीं से महंगाई का व्यापक प्रभाव शुरू होता है। जब माल ढुलाई महंगी होती है तो सब्जियां,फल, दूध,अनाज, दवाइयां,निर्माण सामग्री और अन्य उपभोक्ता वस्तुएं भी महंगी हो जाती हैं। इस प्रक्रिया को अर्थशास्त्र में लागत-प्रेरित महंगाई कहा जाता है। इसका असर विशेष रूप से मध्यम वर्ग और निम्न आय वर्ग पर पड़ता है,क्योंकि उनकी आय सीमित होती है जबकि खर्च लगातार बढ़ते जाते हैं।

ग्रामीण भारत में पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों का प्रभाव और भी गहरा होता है। खेती-किसानी आज भी बड़ी मात्रा में डीज़ल आधारित मशीनों और उपकरणों पर निर्भर है। ट्रैक्टर, सिंचाई पंप, कटाई मशीनें और कृषि उत्पादों का परिवहन–सभी में ईंधन की आवश्यकता होती है। जब डीज़ल महंगा होता है तो कृषि लागत बढ़ जाती है। छोटे और सीमांत किसान, जिनकी आय पहले से ही सीमित होती है,इस बढ़ती लागत का सबसे अधिक बोझ उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की लागत भी बढ़ जाती है। अक्सर किसान अपने उत्पादों का मूल्य स्वयं निर्धारित नहीं कर पाते और उन्हें बिचौलियों या थोक व्यापारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में परिवहन लागत बढ़ने का दबाव किसानों की आय को और कम कर सकता है। परिणामस्वरूप ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर दोहरा प्रभाव पड़ता है–उत्पादन लागत बढ़ती है और लाभ घटता है।

शहरी मध्यम वर्ग भी इस महंगाई से अछूता नहीं रहता। आज का शहरी जीवन डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन खरीदारी,भोजन वितरण और निजी परिवहन पर काफी हद तक निर्भर हो चुका है। लेकिन इन सभी सेवाओं के पीछे परिवहन लागत एक महत्वपूर्ण तत्व है। चाहे कोई ऑनलाइन भोजन मंगाए या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म से सामान खरीदे,अंततः उसे पहुंचाने वाला वाहन ईंधन पर ही निर्भर होता है। इसलिए पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि धीरे-धीरे उपभोक्ता के दैनिक खर्च को बढ़ाती जाती है।

पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर चर्चा करते समय एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी उठता है कि भारत ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में कितना आत्मनिर्भर है। पिछले वर्षों में सरकार ने रणनीतिक तेल भंडार विकसित करने और ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने के प्रयास किए हैं। इससे आपूर्ति संकट की स्थिति में कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन यह दीर्घ कालिक समाधान नहीं है। जब तक देश आयातित तेल पर अत्यधिक निर्भर रहेगा, तब तक वैश्विक बाजार की अस्थिरता का प्रभाव घरेलू अर्थ व्यवस्था पर पड़ता रहेगा।

यहीं से ऊर्जा स्वाधीनता का प्रश्न सामने आता है। ऊर्जा स्वाधीनता का अर्थ केवल घरेलू तेल उत्पादन बढ़ाना नहीं है, बल्कि वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को मजबूत करना भी है। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन,जैव ईंधन और विद्युत आधारित परिवहन व्यवस्था इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अभी भी लंबा रास्ता तय करना बाकी है।

परिवहन नीति भी इस पूरे विमर्श का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली मजबूत, सुलभ और भरोसेमंद हो तो निजी वाहनों पर निर्भरता कम की जा सकती है। मेट्रो,बस रैपिड ट्रांजिट,उपनगरीय रेल और सुरक्षित साइकिल मार्ग जैसे विकल्प न केवल ईंधन की खपत कम कर सकते हैं,बल्कि प्रदूषण और यातायात जाम जैसी समस्याओं को भी कम कर सकते हैं। दुर्भाग्यवश, देश के अनेक शहरों और अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाओं का अभाव अभी भी महसूस किया जाता है।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नीति भी इसी संदर्भ में महत्वपूर्ण है। पेट्रोल और डीज़ल पर निर्भरता कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का विकल्प माना जा रहा है। हालांकि उनकी स्वीकार्यता बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग अवसंरचना,बैटरी लागत और ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। यदि सरकारें इस क्षेत्र में निवेश बढ़ाती हैं और आवश्यक बुनियादी ढांचा विकसित करती हैं, तो आने वाले वर्षों में तेल पर निर्भरता को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

पेट्रोल की कीमतों का एक पर्यावरणीय आयाम भी है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण की प्रमुख वजहों में से एक है। बढ़ती ईंधन कीमतें कई बार लोगों को वैकल्पिक परिवहन साधनों की ओर आकर्षित करती हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब वे विकल्प वास्तव में उपलब्ध और सुविधाजनक हों। केवल कीमत बढ़ा देने से पर्यावरणीय लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सकते; इसके लिए व्यापक और समन्वित नीति की आवश्यकता होती है।

राजनीतिक स्तर पर पेट्रोल की कीमतें हमेशा संवेदनशील मुद्दा रही हैं। विपक्ष अक्सर बढ़ती कीमतों को सरकार की विफलता के रूप में प्रस्तुत करता है,जबकि सरकारें वैश्विक परिस्थितियों और बाजार की मजबूरियों का हवाला देती हैं। वास्तविकता इन दोनों के बीच कहीं स्थित है। यह सच है कि अंतरराष्ट्रीय तेल कीमतों पर किसी एक देश का पूर्ण नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि कर नीति, ऊर्जा निवेश और परिवहन सुधार जैसे क्षेत्रों में सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

इसलिए पेट्रोल की कीमतों पर बहस केवल आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि ऊर्जा नीति,कर संरचना, परिवहन व्यवस्था और पर्यावरणीय लक्ष्यों को एकीकृत दृष्टिकोण के साथ देखा जाए। यदि नीति निर्माण केवल तात्कालिक राजनीतिक लाभ या राजस्व आवश्यकताओं तक सीमित रहेगा, तो दीर्घकालिक समाधान सामने नहीं आ पाएंगे।

अभिजात क्लबों पर सरकारी निगरानी समय की मांग

सुभाष बुड़ावन वाला,रतलाम.मध्यप्रदेश

केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में दिल्ली ग्यामखाना क्लब के प्रशासनिक नियंत्रण को अपने हाथ में लेने का निर्णय केवल एक कानूनी कार्रवाई नहीं,बल्कि भारतीय समाज में लंबे समय से मौजूद अभिजात विशेषाधिकारों पर गंभीर प्रश्न है। यह कदम उन तथाकथित प्रतिष्ठित क्लबों की कार्यप्रणाली की ओर ध्यान आकर्षित करता है, जो दशकों से सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सीमित वर्ग के हितों के लिए करते आ रहे हैं।भारत में जिमखाना और एलीट क्लबों की संस्कृति ब्रिटिश शासन की देन है। अंग्रेज अधिकारियों ने अपने सामाजिक और मनोरंजन केंद्रों के रूप में इन क्लबों की स्थापना की थी। इनके लिए सरकारी जमीनें बेहद कम कीमत पर उपलब्ध कराई गईं। स्वतंत्रता के बाद अपेक्षा थी कि लोकतांत्रिक भारत इन संस्थानों को जनसामान्य के लिए अधिक खुला और समावेशी बनाएगा, लेकिन वास्तविकता इसके विपरीत रही। सत्ता, नौकरशाही और आर्थिक रूप से मजबूत वर्ग ने इन संस्थानों पर अपना प्रभुत्व बनाए रखा और क्लबों का चरित्र लगभग औपनिवेशिक ही बना रहा।

आज भी देश के अनेक प्रतिष्ठित क्लबों में सदस्यता आम नागरिक की पहुंच से बाहर है। कई क्लबों में वर्षों लंबी प्रतीक्षा सूची, भारी सदस्यता शुल्क और प्रभावशाली लोगों की सिफारिश जैसी व्यवस्थाएं लागू हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि ये संस्थान सामाजिक समानता नहीं, बल्कि विशिष्ट वर्गीय पहचान को मजबूत करते हैं। लोकतंत्र में सार्वजनिक संसाधनों पर सभी नागरिकों का समान अधिकार होना चाहिए, किंतु इन क्लबों में यह भावना दिखाई नहीं देती।

सबसे चिंताजनक पक्ष इन क्लबों के पास मौजूद विशाल भूमि और संपत्तियां हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और लखनऊ जैसे महानगरों में अनेक क्लब हजारों करोड़ रुपये मूल्य की सरकारी या सार्वजनिक जमीन पर अत्यंत कम लीज दरों पर संचालित हो रहे हैं। दूसरी ओर शहरों में बच्चों के खेलने के मैदान, सार्वजनिक पार्क और खेल सुविधाओं की भारी कमी बनी हुई है। ऐसे में यह सवाल स्वाभाविक है कि क्या सार्वजनिक भूमि का उपयोग सीमित लोगों के मनोरंजन और निजी आयोजनों तक सीमित रहना चाहिए?

समाजशास्त्री सी. राइट मिल्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द पावर ईलाईट में सत्ता,नौकरशाही और आर्थिक वर्ग के गठजोड़ का उल्लेख किया था। भारतीय संदर्भ में कई अभिजात क्लब उसी सत्ता-संरचना के प्रतीक दिखाई देते हैं, जहां प्रभावशाली लोग सामाजिक नेटवर्क और संबंधों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शक्ति का निर्माण करते हैं। यही कारण है कि इन संस्थानों की कार्यप्रणाली लंबे समय तक पारदर्शिता और सार्वजनिक समीक्षा से दूर रही।विश्व के कई देशों में अब पुराने एलीट क्लबों को सार्वजनिक उपयोग के लिए परिवर्तित किया जा रहा है। कहीं उन्हें सांस्कृतिक केंद्र बनाया गया है तो कहीं खेल और सामुदायिक गतिविधियों के लिए खोला गया है। भारत में भी आवश्यकता है कि सरकार इन क्लबों की सदस्यता प्रक्रिया, वित्तीय लेनदेन, भूमि उपयोग और प्रशासनिक संरचना की निष्पक्ष समीक्षा करे। यदि कोई संस्था सार्वजनिक भूमि पर संचालित हो रही है, तो उसकी जवाबदेही भी जनता के प्रति होनी चाहिए।लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक संसाधनों के न्यायपूर्ण उपयोग से मजबूत बनता है। देश की बहुमूल्य जमीनें कुछ चुनिंदा लोगों के विशेषाधिकार का माध्यम नहीं बन सकतीं। इसलिए अभिजात क्लबों पर सरकारी निगरानी और पारदर्शिता सुनिश्चित करना आज समय की सबसे बड़ी मांग बन चुका है।

सूचना
समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।
-सम्पादक

सरगुजा की आध्यात्मिक विरासत को राष्ट्रीय पहचान की तैयारी

केंद्र सरकार की 'ज्ञान भारतम्' योजना के तहत दुर्लभ संस्कृत पाण्डुलिपियों का हुआ परीक्षण,संरक्षण और डिजिटाइजेशन की प्रक्रिया होगी शुरू....

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
सरगुजा की सांस्कृतिक,आध्यात्मिक और तांत्रिक परंपरा से जुड़ी एक अनमोल धरोहर अब राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित होने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शहर के प्रतिष्ठित पाण्डेय परिवार के पास पीढ़ियों से सुरक्षित रखी गई दुर्लभ हस्तलिखित संस्कृत पाण्डुलिपियों का केंद्र सरकार की टीम ने गहन अवलोकन किया। 'ज्ञान भारतम्' योजना के तहत पहुंचे प्रशासनिक और सांस्कृतिक विशेषज्ञों ने इन ग्रंथों को भारतीय ज्ञान परंपरा की अमूल्य धरोहर बताया। इस अवसर पर सरगुजा संभाग आयुक्त (कमिश्नर) श्री नरेंद्र दुग्गा, संयुक्त कलेक्टर शारदा अग्रवाल, उप आयुक्त सहित कई प्रशासनिक अधिकारी एवं जगदलपुर से आए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि मौजूद रहे। अधिकारियों ने लगभग तीन घंटे तक पाण्डुलिपियों का परीक्षण, जियो टैगिंग और दस्तावेजीकरण किया। टीम ने बताया कि अगले चरण में इन दुर्लभ ग्रंथों की हाई रिजोल्यूशन स्कैनिंग की जाएगी,ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए इन्हें सुरक्षित रखा जा सके। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय की विशेषज्ञ टीम इनके संरक्षण और संवर्धन का कार्य करेगी।

तंत्र साधना और ज्योतिष से जुड़े हैं ग्रंथ

परीक्षण के दौरान जिन ग्रंथों का अवलोकन किया गया उनमें 'वन दुर्गा ', 'प्रत्यंगिरा विधि ', 'भैरव तंत्र' और 'भुजंग प्रयात छंद' आधारित पाण्डुलिपियां प्रमुख हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये ग्रंथ सामान्य साहित्य नहीं बल्कि तंत्र साधना, ज्योतिष और आध्यात्मिक साधना की अत्यंत विशिष्ट परंपरा से जुड़े दस्तावेज हैं। विशेषज्ञों ने माना कि इस प्रकार की हस्तलिखित पाण्डुलिपियां अब बहुत कम परिवारों में सुरक्षित बची हैं। कई ग्रंथ तो समय के साथ नष्ट हो चुके हैं, ऐसे में इन पाण्डुलिपियों का संरक्षित मिलना अपने आप में बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है।

पीढ़ियों से सुरक्षित रखी गई हैं दुर्लभ पाण्डुलिपियां : इन पाण्डुलिपियों को वर्तमान में राजेश पाण्डेय 'अभ्र' के बड़े भाई राकेश पाण्डेय द्वारा सुरक्षित रखा गया है। बताया गया कि ये सभी ग्रंथ उनके प्रपितामह पंडित चतुर प्रसाद शर्मा द्वारा संस्कृत भाषा में स्वयं लिखे गए थे। कई पृष्ठों पर विक्रम संवत, लेखक का नाम और पारंपरिक चिह्न स्पष्ट रूप से अंकित हैं, जिससे इनकी ऐतिहासिक प्रमाणिकता और महत्व और अधिक बढ़ जाता है। पाण्डुलिपियों की स्थिति भले समय के साथ जर्जर हुई हो, लेकिन उनमें अंकित ज्ञान आज भी सुरक्षित है। अधिकारियों ने अवलोकन के दौरान पाया कि लेखन शैली, प्रयुक्त भाषा और संरचना अत्यंत प्राचीन भारतीय परंपरा को दर्शाती है।

कामाख्या पीठ से जुड़ा है परिवार का इतिहास : राजेश पाण्डेय 'अभ्र' ने बताया कि उनके प्रपितामह और उनके भाई को तत्कालीन राजपरिवार स्वयं असम स्थित प्रसिद्ध कामाख्या पीठ से सरगुजा लेकर आया था। दोनों गुरु-शिष्य परंपरा से जुड़े तंत्र और ज्योतिष विद्या के विशिष्ट जानकार थे। उनकी विद्वता और साधना से प्रभावित होकर तत्कालीन राजा ने उन्हें राजपुरोहित का दायित्व सौंपा था। उन्होंने बताया कि परिवार ने इन पाण्डुलिपियों को केवल धार्मिक ग्रंथ मानकर नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में संभालकर रखा। वर्षों तक इन्हें सुरक्षित रखने के पीछे उद्देश्य यही था कि आने वाली पीढ़ियां भारतीय ज्ञान परंपरा की वास्तविक विरासत को समझ सकें।

'ज्ञान भारतम्' योजना से मिलेगी नई पहचान

केंद्र सरकार द्वारा संचालित 'ज्ञान भारतम्' योजना का उद्देश्य देशभर में बिखरी दुर्लभ पाण्डुलिपियों और पारंपरिक ज्ञान को खोजकर उसका डिजिटाइजेशन और संरक्षण करना है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की वास्तविक बौद्धिक विरासत केवल पुस्तकालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों परिवारों और आश्रमों में आज भी ऐसी दुर्लभ पाण्डुलिपियां सुरक्षित हैं। सरगुजा में मिले इन ग्रंथों को भी इसी दिशा में महत्वपूर्ण खोज माना जा रहा है। अधिकारियों ने संकेत दिए कि परीक्षण और स्कैनिंग के बाद इन पाण्डुलिपियों को राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत किया जा सकता है।

घर का माहौल बना उत्सव जैसा

अधिकारियों और विशेषज्ञों की मौजूदगी के दौरान पूरा घर उत्सव के माहौल में नजर आया। परिवार के अधिकांश सदस्य इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। किसी ने इसे पूर्वजों के ज्ञान का सम्मान बताया तो किसी ने इसे सरगुजा की सांस्कृतिक पहचान का गौरवपूर्ण पल कहा। परिवार का कहना है कि वर्षों से संभालकर रखी गई यह विरासत अब देशभर के शोधकर्ताओं और विद्वानों तक पहुंचेगी, यही उनके पूर्वजों के ज्ञान को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

शराब पीकर वाहन चलाना पड़ा महंगा...बतौली,उदयपुर और यातायात पुलिस की कार्रवाई,6 मामलों में कोर्ट ने लगाया 61 हजार का जुर्माना

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)।
सरगुजा पुलिस द्वारा शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में थाना बतौली,उदयपुर एवं यातायात पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 सहित अन्य धाराओं के तहत 6 वाहन चालकों पर कार्रवाई की। सभी मामलों में माननीय न्यायालय ने कुल 61 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देश पर जिले में शराब पीकर वाहन चलाने,खतरनाक ड्राइविंग और यातायात नियमों के उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान नशे की हालत में वाहन चलाते पाए गए चालकों का मेडिकल परीक्षण कराया गया,जिसमें शराब सेवन की पुष्टि हुई। इसके बाद संबंधित वाहनों को जब्त कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

इन चालकों पर हुई कार्रवाई : थाना बतौली पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 ED 6175 के चालक भूपेन्द्र पैंकरा निवासी सोनतराई थाना सीतापुर के खिलाफ कार्रवाई की। वहीं थाना उदयपुर पुलिस ने चारपहिया वाहन क्रमांक CG 12 BJ 7332 के चालक संजीव सरकार निवासी मोरगा जिला कोरबा तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EB 3368 के चालक सिंग साय निवासी सोनतराई थाना उदयपुर पर कार्रवाई की। इसी तरह यातायात पुलिस ने मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 EF 6368 के चालक संतोष सिंह निवासी गांधीनगर,मोटरसाइकिल क्रमांक CG 15 DY 1816 के चालक गोलक महालदार निवासी भगवानपुर तथा मोटरसाइकिल क्रमांक CG 28 रु 4915 के चालक कलिन्दर कुजूर निवासी बेलकोटा थाना बतौली के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।

कोर्ट ने लगाया 61 हजार का अर्थदंड : सभी मामलों में वाहन चालकों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां 25 मई 2026 को सुनवाई के दौरान अलग-अलग प्रकरणों में 10-10 हजार रुपए तथा एक मामले में 11 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया गया। इस प्रकार कुल 61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया।

हादसे ने छीना सहारा,वेतन बंद होने से टूटा परिवार

पैरालाइसिस से जूझ रहे डाटा एंट्री ऑपरेटर ने व्हीलचेयर पर पहुंचकर कलेक्टर से लगाई मदद की गुहार

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
कभी सरकारी दफ्तर में जिम्मेदारी से काम करने वाला एक कर्मचारी आज व्हीलचेयर पर जिंदगी काटने को मजबूर है। सड़क हादसे ने न सिर्फ उसके शरीर का आधा हिस्सा छीन लिया, बल्कि नौकरी और सम्मान के साथ परिवार की खुशियां भी बिखेर दीं। सरगुजा जिले के धौरपुर तहसील में पदस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर बुधेश्वर प्रसाद सिदार पिछले छह वर्षों से पैरालाइसिस की पीड़ा झेल रहे हैं। हादसे के बाद से उनका वेतन बंद है और अब पूरा परिवार आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। शक्ति जिले के डबरा तहसील अंतर्गत ग्राम तुलसीडीह निवासी 35 वर्षीय बुधेश्वर प्रसाद सिदार की नियुक्ति वर्ष 2014 में व्यापम के माध्यम से डाटा एंट्री ऑपरेटर पद पर हुई थी। वे धौरपुर तहसील कार्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे थे। वर्ष 2019 में एक सड़क हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा इतना भयावह था कि उनके शरीर का बायां हिस्सा पैरालाइसिस का शिकार हो गया। इसके बाद उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। परिजनों ने बताया कि हादसे के बाद उन्हें तत्काल रायपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। करीब तीन माह तक उनका इलाज चला। इलाज और ऑपरेशन में 24 लाख रुपए से अधिक खर्च हो गए। बेटे को बचाने के लिए परिवार ने अपनी जमीन बेच दी। मां और पत्नी के जेवर तक बेचने पड़े। परिवार को उम्मीद थी कि इलाज के बाद हालात सुधर जाएंगे, लेकिन बुधेश्वर आज भी व्हीलचेयर के सहारे जीवन जी रहे हैं। इधर, हादसे के बाद से विभाग ने उनका वेतन बंद कर दिया। 'नो वर्क, नो पेमेंट' के आधार पर वर्ष 2019 से उन्हें भुगतान नहीं किया जा रहा है। लगातार वेतन बंद रहने से परिवार की आर्थिक स्थिति पूरी तरह डगमगा गई है। दवा,इलाज और घर खर्च चलाना मुश्किल हो गया है। परिवार अब रिश्तेदारों और परिचितों की मदद से किसी तरह गुजर-बसर कर रहा है।

मंगलवार को बुधेश्वर अपनी मां,बहन और जीजा के साथ व्हीलचेयर पर कलेक्टर जनदर्शन पहुंचे। जनदर्शन में मौजूद लोगों की नजर जैसे ही व्हीलचेयर पर बैठे बुधेश्वर पर पड़ी,माहौल कुछ देर के लिए भावुक हो उठा। उन्होंने कलेक्टर से वेतन बहाल कराने और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की। परिवार का कहना है कि यदि समय रहते मदद नहीं मिली तो आगे इलाज कराना भी संभव नहीं होगा। बुधेश्वर की आंखों में दर्द साफ नजर आ रहा था। कभी खुद अपने पैरों पर खड़े होकर नौकरी करने वाला युवक आज दूसरों के सहारे चलने को मजबूर है। परिवार को अब प्रशासन से संवेदनशील पहल और राहत की उम्मीद है, ताकि जिंदगी की लड़ाई लड़ रहे बुधेश्वर को कुछ सहारा मिल सके।

नसबंदी ऑपरेशन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने का आरोप

मेडिकल कॉलेज अस्पताल में परिजनों का हंगामा,डॉक्टर से स्पष्टीकरण लेने की बात

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
मेडिकल कॉलेज अस्पताल में नसबंदी ऑपरेशन के दौरान एक महिला मरीज को थप्पड़ मारने का आरोप सामने आया है। घटना मंगलवार की है। ऑपरेशन के बाद महिला ने अपने पति और परिजनों को पूरी बात बताई, जिसके बाद अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। परिजनों ने संबंधित महिला डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार शहर की एक महिला नसबंदी कराने मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंची थी। यहां ड्यूटी पर पदस्थ महिला डॉक्टर द्वारा उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। महिला का आरोप है कि ऑपरेशन के दौरान उसे काफी दर्द हो रहा था। नसबंदी वाले हिस्से को सुन्न किया गया था, लेकिन ऊपर के हिस्से में दर्द महसूस हो रहा था। इस दौरान उसने डॉक्टर को दर्द होने की जानकारी दी। महिला मरीज का कहना है कि दर्द की वजह से उसने पैर हिलाया तो डॉक्टर नाराज हो गईं। आरोप है कि डॉक्टर ने रूखे अंदाज में बात करते हुए कहा कि 'यहां क्यों आ जाते हो' और गुस्से में उसे थप्पड़ मार दिया। महिला ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान वह दर्द से परेशान थी और ऊपर से डॉक्टर का व्यवहार उसे और परेशान कर गया। घटना की जानकारी मिलते ही महिला के पति और अन्य परिजन अस्पताल पहुंच गए। उन्होंने अस्पताल परिसर में हंगामा करते हुए संबंधित डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। महिला के पिता पुनील मंडल ने कहा कि मरीज इलाज कराने अस्पताल आते हैं, ऐसे में डॉक्टरों को धैर्य रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि डॉक्टर ही इस तरह का व्यवहार करेंगे तो मरीज कहां जाएगा। उन्होंने दोषी डॉक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। हंगामे की सूचना पर अस्पताल में पदस्थ वरिष्ठ डॉक्टर मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। अस्पताल प्रबंधन की ओर से डॉक्टर जेके रेलवानी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान पहली बार एनेस्थीसिया का डोज पर्याप्त नहीं हो पाया होगा, जिसके कारण महिला को दर्द महसूस हुआ। बाद में दोबारा डोज देने के बाद ऑपरेशन पूरा किया गया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टरों और स्टाफ को मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए लिखित निर्देश भी जारी किए जाएंगे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति न बने। वहीं महिला डॉक्टर पर लगे थप्पड़ मारने के आरोप को लेकर उन्होंने कहा कि संबंधित डॉक्टर से स्पष्टीकरण लिया जाएगा।

शराब दुकान के विरोध में महिलाओं का प्रदर्शन

जनदर्शन में पहुंचीं ग्रामीण महिलाएं,कलेक्ट्रेट परिसर में की नारेबाजी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
दरिमा क्षेत्र में एक सप्ताह पूर्व शुरू हुई अंग्रेजी शराब दुकान का विरोध अब तेज हो गया है। मंगलवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और पुरुष जनदर्शन में पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान बंद कराने की मांग की। इस दौरान महिलाओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर नारेबाजी भी की। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब दुकान खुलने से माहौल खराब हो रहा है। इसका सबसे ज्यादा असर महिलाओं और युवाओं पर पड़ रहा है। गांव में विवाद और सामाजिक समस्याएं बढ़ने लगी हैं। महिलाओं ने कहा कि शराब बिक्री शुरू होने के बाद परिवारों का माहौल बिगड़ रहा है और असुरक्षा की भावना बढ़ी है। जनदर्शन में पहुंचे ग्रामीणों ने कलेक्टर अजीत बसंत को ज्ञापन सौंपकर शराब दुकान बंद कराने की मांग की। महिलाओं का आरोप है कि मुलाकात के दौरान कलेक्टर ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें महतारी वंदन योजना का लाभ मिल रहा है। महिलाओं ने बताया कि वे योजना का लाभ ले रही हैं। इसके बाद कथित तौर पर कलेक्टर ने कहा कि जिस तरह महतारी वंदन योजना सरकार की योजना है, उसी तरह शराब दुकान भी सरकार की नीति के तहत संचालित हो रही है। कलेक्टर की इस बात पर महिलाएं नाराज हो गईं। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और शराब दुकान का कोई संबंध नहीं है। महिलाओं ने स्पष्ट कहा कि उन्हें योजना से ज्यादा गांव में शांति और सुरक्षा चाहिए। उनका कहना था कि गांव में शराब दुकान बंद होना जरूरी है। विरोध के दौरान महिलाओं ने 'शराब दुकान बंद करो ','गांव बचाओ' जैसे नारे लगाए। कुछ देर तक कलेक्ट्रेट परिसर में माहौल गर्म रहा। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि शराब दुकान बंद नहीं की गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।

पूर्व सैनिकों का किया गया सम्मान...पूर्व सैनिकों एवं सैनिक परिवारों के कल्याण संबंधी विषयों पर हुई चर्चा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
जिला सैनिक बोर्ड, अम्बिकापुर की बैठक का आयोजन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। बैठक में पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण, सुविधाओं तथा विभिन्न सहायता योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला पंचायत सीईओ श्री विनय कुमार अग्रवाल एवं डिप्टी कलेक्टर सूरजपुर श्री सुनील अग्रवाल उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कैप्टन उमेद सिंह चारण (सेवानिवृत्त) ने पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता एवं विभिन्न सुविधाओं की जानकारी दी। बैठक में लेफ्टिनेंट कर्नल एम.के. तिवारी (सेवानिवृत्त), न्यूरो सर्जन जीवन ज्योति अस्पताल द्वारा पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के उपचार हेतु सीजीएचएस दर एवं ईसीएचएस के संलग्नीकरण के संबंध में जानकारी साझा की गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री राजेश अग्रवाल ने संबोधित करते हुए कहा कि देश की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों पर पूरे देश को गर्व है। उन्होंने कहा कि परिवार के किसी सदस्य को खोने का दर्द वही परिवार समझ सकता है जिसने अपना प्रियजन देश सेवा में समर्पित किया हो।

जिले में अवैध खनिज परिवहन एवं भंडारण पर खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई

भंडारणकर्ताओं को नोटिस जारी,वाहन किए गए जप्त

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग द्वारा अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज अधिकारी श्री अनिल कुमार साहू से प्राप्त जानकारी के अनुसार बीते तीन दिनों के भीतर सीतापुर एवं लखनपुर तहसील क्षेत्रों में बड़ी कार्रवाई करते हुए कई अवैध भंडारण स्थलों और वाहनों पर कार्यवाही की गई। सीतापुर तहसील अंतर्गत ग्राम प्रतापगढ़, खड़ादोरना, भवराडाड एवं आमाटोली क्षेत्र में जांच के दौरान गौण खनिज रेत के अवैध भंडारण के छह मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की गई। संबंधित भंडारणकर्ताओं को मौके पर नोटिस जारी किया गया। वहीं ग्राम आमादरहा क्षेत्र में एक अवैध ईंट मिट्टी एवं कोयला भंडारण पाए जाने पर भी भण्डारणकर्ता को नोटिस जारी किया गया। विभाग द्वारा अवैध रेत परिवहन करते पाए गए तीन ट्रैक्टर वाहनों को जब्त कर थाना सीतापुर की अभिरक्षा में सौंप दिया है। इसी कड़ी में 24 मई 2026 को लखनपुर तहसील के ग्राम भौराडांड में जांच के दौरान अवैध रेत परिवहन करते हुए दो ट्रैक्टर एवं दो टीपर वाहन पकड़े गए। साथ ही अवैध ईंट मिट्टी परिवहन में लगे एक ट्रैक्टर वाहन को भी जप्त कर थाना लखनपुर की अभिरक्षा में सौंपा गया।

एनएच-130 पर भीषण सड़क हादसा...पिकअप क्लीनर की मौत

खड़ी ट्राला से भिड़ी आम लोड पिकअप,गैस कटर से काटकर निकाला गया शव

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,26 मई 2026
(घटती-घटना)।
नेशनल हाईवे-130 पर सोमवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे में पिकअप वाहन के क्लीनर की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उदयपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम डांडगांव स्थित प्रिंस ढाबा के पास सुबह करीब 5 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि रायपुर से अंबिकापुर की ओर आम लोडकर आ रही पिकअप विपरीत दिशा से तेज रफ्तार में आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे खड़ी ट्राला से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पिकअप का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। वाहन में सवार क्लीनर केबिन में बुरी तरह फंस गया और दबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान रायपुर के गुढियारी क्षेत्र निवासी खुर्सी के रूप में हुई है। हादसे के बाद सामने से आ रहा हाईवा चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही उदयपुर थाना प्रभारी शिशिरकांत सिंह, सहायक उप निरीक्षक लीनूस लकड़ा और डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची। हादसा इतना भयावह था कि पिकअप में फंसे शव को बाहर निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने गैस कटर की मदद से वाहन की बॉडी काटकर करीब सुबह 10 बजे शव बाहर निकाला। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उदयपुर भेजा गया।

पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। हादसे में पिकअप चालक को मामूली चोटें आई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और फरार हाईवा चालक की तलाश की जा रही है। इधर, स्थानीय लोगों ने नेशनल हाईवे-130 पर लगातार हो रहे सड़क हादसों पर नाराजगी जताई है। लोगों का कहना है कि हाईवे पर बेलगाम रफ्तार और भारी वाहनों की लापरवाही के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके सुरक्षा व्यवस्था और यातायात नियंत्रण को लेकर ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।

CMYK

किसानों की खाद या नेताओं-बिचौलियों की दावत?

1800 बोरी खाद बेचने की कबूली बात से मचा हड़कंप

खाद घोटाले में खुलती जा रही नई परतें

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,26 मई 2026 (घटती-घटना)। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति में हुए बहुचर्चित खाद घोटाले ने अब बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक रूप लेना शुरू कर दिया है, समिति प्रबंधक अखिल चंद्र की गिरफ्तारी के बाद पुलिस पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आरोप है कि किसानों के लिए आई हजारों बोरी खाद बिचौलियों के माध्यम से बेच दी गई। पुलिस ने दो दिन पहले अखिल चंद्र को जिल्दा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था, पूछताछ में उसने कथित रूप से स्वीकार किया कि करीब 1800 बोरी खाद जिल्दा निवासी तुलसी साहू को बेची गई थी, वहीं लगभग 1200 बोरी खाद पोड़ी क्षेत्र के एक अन्य बिचौलिया को खपाए जाने की बात भी सामने आई है, हालांकि उस व्यक्ति का नाम अब तक सार्वजनिक नहीं किया गया है।

201 बोरी बरामदगी के बाद भी कार्रवाई अधूरी?- शुक्रवार को बैमा-सागरपुर पुलिस ने अखिल चंद्र की निशानदेही पर 201 बोरी खाद बरामद की,इस दौरान भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष शुभम जायसवाल और कांग्रेस ब्लॉक उपाध्यक्ष विजय जायसवाल को भी पूछताछ के लिए लाया गया था,लेकिन बाद में दोनों को छोड़ दिया गया, अब ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि जब खाद बरामद हुई तो फिर हिरासत में लिए गए लोगों को किस आधार पर छोड़ा गया? क्या कार्रवाई राजनीतिक दबाव में प्रभावित हो रही है? व्यंग्य यह भी है कि प्रदेश स्तर पर 350 बोरी खाद जब्ती की बात कही जा रही है, जबकि स्थानीय पुलिस सिर्फ 201 बोरी खाद बरामद होने की जानकारी दे रही है। ऐसे में आंकड़ों का यह अंतर भी संदेह पैदा कर रहा है।

कई नाम आए सामने, जांच पर उठे सवाल-

मामले में जिलीबांध निवासी संत कुमार जायसवाल का नाम भी सामने आया है, जिन्हें करीब 50 बोरी खाद बेचे जाने की चर्चा है, वहीं पोड़ी पंचायत के बरपारा निवासी शिक्षक सतीश साहू का नाम भी कथित खरीदारों में शामिल बताया जा रहा है, जांच के दौरान तेलईमुंडा, जिला सूरजपुर निवासी रमेश साहू को भी पुलिस पूछताछ के लिए पोड़ी चौकी लाई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन लोगों के पास से खाद बरामद होने की बात सामने आई, उनमें से कई को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया।

ग्रामीणों में नाराजगी, निष्पक्ष जांच की मांग

घोटाले को लेकर किसानों और ग्रामीणों में भारी आक्रोश है,लोगों का आरोप है कि किसानों के लिए आई खाद को संगठित तरीके से बिचौलियों तक पहुंचाया गया और अब पूरे मामले को दबाने की कोशिश हो रही है, ग्रामीणों ने मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर सभी जिम्मेदार लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे उनका राजनीतिक या सामाजिक रसूख कितना भी बड़ा क्यों न हो।

आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण मामले में तीन आरोपी गिरफ्तार

गांधीनगर पुलिस की कार्रवाई,मारपीट से आहत युवक ने फांसी लगाकर की थी आत्महत्या

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा जिले के थाना गांधीनगर क्षेत्र में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोप है कि विवाह कार्यक्रम के दौरान आरोपियों द्वारा मारपीट किए जाने से आहत युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश अग्रवाल के निर्देशन में सरगुजा पुलिस द्वारा मामले की जांच करते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

मां को नचाने की बात पर हुआ विवाद : पुलिस के अनुसार थाना गांधीनगर में दर्ज मर्ग क्रमांक 37/2026 की जांच के दौरान पता चला कि मृतक रूकचंद नागेश (25) निवासी सरगवां पतरापारा 27 अप्रैल 2026 को गांव में आयोजित विवाह कार्यक्रम में शामिल होने गया था। कार्यक्रम में डीजे साउंड पर ग्रामीण नाच रहे थे। इसी दौरान आरोपियों ने मृतक की मां कबिलासो को भी नाचने के लिए कहा...जिसका मृतक ने विरोध किया। इसी बात को लेकर आरोपी रामप्रसाद,राजनाथ और अजीत ने मृतक के साथ मारपीट की। घटना से दुःखी और आहत होकर रूकचंद रोते हुए रात करीब 3 बजे घर पहुंचा और अपनी बहन सुमरी नागेश को पूरी घटना बताई। इसके कुछ देर बाद उसने गांव के पीपल पेड़ में ड्रीप पाइप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

तीनों आरोपी गिरफ्तार : मामले की जांच और गवाहों के बयान के आधार पर थाना गांधीनगर पुलिस ने अपराध क्रमांक 277/2026 के तहत धारा 108, 3(5) बीएनएस में प्रकरण दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी रामप्रसाद उर्फ रित्रा (28), अजीत कुमार (32) एवं राजनाथ तिर्की (40) निवासी सरगवां थाना गांधीनगर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जहां उन्होंने घटना में संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस ने तीनों आरोपियों को 25 मई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।

इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका : प्रकरण के निराकरण में थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी, उपनिरीक्षक दिलीप दुबे, प्रधान आरक्षक इमरान गालिब एवं सैनिक रोशन गुप्ता की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

आश्वासन के बाद टला बरियों चक्काजाम

ग्रामीणों की चेतावनी-वादा पूरा नहीं हुआ तो होगा उग्र आंदोलन

-संवाददाता-

राजपुर/बरियों,26 मई 2026 (घटती-घटना)। बलरामपुर जिले के राजपुर ब्लॉक अंतर्गत बरियों क्षेत्र से गुजर रही निर्माणाधीन एनएच-343 सड़क में उड़ती धूल और निर्माण कार्य की धीमी रफ्तार को लेकर ग्रामीणों और व्यापारियों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही थी। बधिमा, बरियों,चारपारा और ककना सहित आसपास के गांवों के लोगों ने 27 मई को बरियों में चक्काजाम करने की चेतावनी दी थी,लेकिन प्रशासन और एनएच विभाग के आश्वासन के बाद आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को प्रशासन,एनएच विभाग और ग्रामीणों के बीच अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजपुर, तहसीलदार बरियों,पुलिस चौकी प्रभारी बरियों, एनएच-343 के एसडीओ, साइड इंजीनियर और प्रोजेक्ट मैनेजर मौजूद रहे। वहीं बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय व्यापारी भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने बैठक में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही, धूल प्रदूषण और नियमित पानी छिड़काव नहीं होने की समस्या को प्रमुखता से उठाया। ग्रामीणों का कहना था कि भारी वाहनों की लगातार आवाजाही के कारण पूरे क्षेत्र में दिनभर धूल का गुबार बना रहता है, जिससे घरों, दुकानों और स्कूलों में रहना मुश्किल हो गया है। धूल के कारण बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों को सांस संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापारियों ने भी बताया कि धूल के कारण ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई शिकायतों के बावजूद निर्माण एजेंसी द्वारा नियमित पानी का छिड़काव नहीं कराया जा रहा है।

नियमित पानी छिड़काव का दिया आश्वासन : ग्रामीणों और व्यापारियों के कड़े रुख को देखते हुए प्रशासन एवं एनएच विभाग के अधिकारियों ने निर्माणाधीन सड़क पर नियमित पानी छिड़काव कराने और सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने का भरोसा दिलाया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद 27 मई को प्रस्तावित चक्काजाम को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया।

वादा पूरा नहीं हुआ तो होगा बड़ा आंदोलन : हालांकि ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन पर अमल नहीं हुआ और धूल नियंत्रण की व्यवस्था नियमित नहीं की गई,तो आने वाले समय में बड़ा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि वे विकास कार्यों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन आम लोगों के स्वास्थ्य और जीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों ने मांग की कि सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी सभी नियमों का पालन कराया जाए ।

साइबर ठगी में इस्तेमाल म्यूल अकाउंट पर सरगुजा पुलिस की बड़ी कार्रवाई

ऑनलाइन ठगी के मामले में एक आरोपी गिरफ्तार,खाते में आए थे 5.73 लाख रुपए

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए जा रहे म्यूल अकाउंट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। आरोपी के बैंक खाते में ऑनलाइन साइबर ठगी की रकम जमा होने की पुष्टि हुई है। मामले में थाना गांधीनगर पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। डीआईजी एवं एसएसपी राजेश कुमार अग्रवाल के निर्देश पर जिले में साइबर अपराधों में संलिप्त आरोपियों की लगातार धरपकड़ की जा रही है। पुलिस मुख्यालय (तकनीकी सेवाएं) नवा रायपुर से मिले निर्देशों के बाद म्यूल अकाउंट के खिलाफ विशेष जांच शुरू की गई थी।

कई राज्यों से दर्ज थीं शिकायतें : जांच के दौरान आईडीबीआई बैंक के खाता क्रमांक 0700104000343329 का बैंक स्टेटमेंट और केवाईसी दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। यह खाता लक्ष्मण नागेश निवासी गुजरवार, अंबिकापुर के नाम पर संचालित पाया गया। पुलिस के अनुसार उक्त खाते के खिलाफ गुजरात,कर्नाटक,पश्चिम बंगाल, तेलंगाना और तमिलनाडु सहित कई राज्यों से साइबर पुलिस पोर्टल पर ऑनलाइन ठगी की शिकायतें दर्ज थीं। जांच में सामने आया कि खाते में साइबर ठगी से संबंधित कुल 5 लाख 73 हजार 999 रुपए जमा हुए थे।

खाते में 33 लाख से अधिक का लेन-देन : विवेचना के दौरान बैंक स्टेटमेंट की जांच में यह भी पता चला कि 21 सितंबर 2024 से 14 अक्टूबर 2024 के बीच खाते में कुल 33 लाख 15 हजार 10 रुपए जमा होकर अन्य खातों में ट्रांसफर किए गए थे। पुलिस पूछताछ में आरोपी लक्ष्मण नागेश ने बताया कि उसने किसी व्यक्ति के कहने पर ऑनलाइन गेमिंग में रकम के लेनदेन के लिए बैंक खाता खुलवाया था। आरोपी ने खाते की पासबुक, एटीएम और सिम दूसरे व्यक्ति को देने के एवज में 10 हजार रुपए नकद लेना स्वीकार किया।

मोबाइल और सिम जब्त

पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 248/2026 के तहत धारा 317(4), 318(4), 3(5) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

प्रतापपुर में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान जारी

मरीजों को दी जा रही स्वास्थ्य शिक्षा और उपचार सामग्री

-संवाददाता-

प्रतापपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत विकासखंड प्रतापपुर में फाइलेरिया उन्मूलन हेतु लगातार गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। इसी क्रम में ग्राम मानी निवासी फाइलेरिया (हाथी पांव) से पीड़ित मरीज राजकुमार कोड़ाकू (35 वर्ष) की सतत मॉनिटरिंग एवं स्वास्थ्य परामर्श किया जा रहा है। वर्ष 2021 में उनकी बीमारी की पहचान होने के बाद से स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित रूप से देखरेख की जा रही है। मंगलवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर मानी में मरीज को बुलाकर फाइलेरिया से बचाव एवं प्रभावित अंग की साफ-सफाई, नियमित व्यायाम, त्वचा की देखभाल और संक्रमण से बचाव संबंधी जानकारी दी गई। साथ ही आवश्यक उपचार सामग्री प्रदान कर मरीज को मार्गदर्शन भी दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने आमजन से अपील करते हुए कहा है कि फाइलेरिया से बचाव हेतु समय-समय पर चलाए जा रहे कार्यक्रमों में अनिवार्य रूप से भाग लें तथा बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह अभियान राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन मिशन को सफल बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित हो रहा है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-6/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण पवन कुमार अग्रवाल, सज्जन अग्रवाल, भजन कुमार अग्रवाल, आ.स्व. धनसी राम अग्रवाल, सभी निवासी चोपड़ापारा जैन मंदिर के पास, था0तह0 अम्बिकापुर जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा तदाशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है, कि आवेदकगण के पिता स्व. धनसी राम अग्रवाल आ.स्व. अमर चंद अग्रवाल, के द्वारा स्वयं संयुक्त स्वामित्व व अधिपत्य की नगर अम्बिकापुर, शीट नं. 03 देवीगंज रोड़ स्थित नजूल भूमि प्लॉट नंबर 1021 / 2 रकबा 0.13 1/2 हे0 भूमि के संबंध में वसीयतनामा दिनांक 25.07.2006 का निष्पादन आवेदकगण के पक्ष में किया गया है। वसीयतकर्ता धनसी राम अग्रवाल आ.स्व. अमर चंद अग्रवाल की मृत्यु दिनांक 13.01.2013 को हो गई है। अतः भूधारक / वसीयतकर्ता की मृत्यु हो जाने उपरांत उक्त वसीयतनामा के आधार पर उक्त आवेदित भूखण्ड से उनका नाम विलोपित कर स्वयं का नाम दर्ज किये जाने हेतु आवेदकगण द्वारा मृत्तक भूधारक के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति मय दस्तावेज सहित आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 109, 110 छ.ग. भू-राजस्व संहिता 1959 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त सबंध में जिस किसी व्यक्ति या संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो वे अपना लिखित दावा / आपत्ति स्वंय अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक- 10/06/2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा / अपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक-26/05/2026 को मेरे न्यायालयीन मुद्रा एंव हस्ताक्षर से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

-संवाददाता-

सूरजपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है, आरोपी ने आबकारी विभाग में भृत्य (चपरासी) की नौकरी लगाने का झांसा देकर एक लाख रुपये की ठगी की थी और फर्जी नियुक्ति आदेश तैयार कर पीड़ित को सौंप दिया था। मामले के अनुसार 10 जुलाई 2018 को प्रार्थी अशोक दास ने थाना प्रेमनगर में शिकायत दर्ज कराई थी कि हेमंत महंत ने आबकारी विभाग में नौकरी लगाने का भरोसा दिलाकर उससे एक लाख रुपये लिए। कुछ समय बाद आरोपी ने नियुक्ति आदेश भी दिया, लेकिन जब प्रार्थी संबंधित विभाग में जानकारी लेने पहुंचा तो दस्तावेज पूरी तरह फर्जी निकला, शिकायत के बाद प्रेमनगर थाना में अपराध क्रमांक 53/18 के तहत धारा 420, 467, 468 और 471 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया, पुलिस ने आरोपी हेमंत महंत पिता सुंदर दास सोनवानी,निवासी ग्राम चंदननगर थाना प्रेमनगर को गिरफ्तार किया,मामले की विवेचना निरीक्षक बसंत लाल सिंह ने की और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीपीओ राजेश सिंह और पंकज कुमार बागड़े ने पैरवी की, सुनवाई के बाद विद्वान न्यायाधीश रूचि मिश्रा ने आरोपी को धोखाधड़ी का दोषी मानते हुए धारा 420 आईपीसी के तहत 3 वर्ष के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई, यह मामला एक बार फिर उन लोगों के लिए चेतावनी माना जा रहा है जो सरकारी नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोहों के झांसे में आ जाते हैं।

थाना के सामने मोबाइल टावर पर युवती ने लगाई फांसी,वीडियो देखने की थी लत

-संवाददाता-

जशपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के कुनकुरी थाना क्षेत्र के धुमाडांड गांव में मंगलवार तड़के एक युवती ने कुनकुरी थाने के सामने स्थित मोबाइल टावर पर चढ़कर फांसी लगा ली। घटना के वक्त युवती मोबाइल पर कुछ वीडियो देख रही थी।परिजनों के अनुसार,नीलिमा लकड़ा पिछले काफी समय से मानसिक रूप से अस्वस्थ थी। उसे मोबाइल पर फांसी लगाने से जुड़े आत्मघाती वीडियो देखने की गंभीर लत थी। मना करने पर भी वह नहीं मानती थी। पूर्व में भी उसने एक बार ऐसा ही आत्मघाती कदम उठाने का प्रयास की थी। घटना से एक दिन पहले वह मां के साथ अस्पताल गई थी, और अचानक लापता हो गई। रात में पुलिस पेट्रोलिंग टीम को मिलने के बाद वह घर की तरफ रवाना हुई थी।

सुपोषण का सपना,भूखे कर्मचारियों के सहारे? मानदेय नहीं मिलने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा

महिला एवं बाल विकास विभाग में बढ़ा असंतोष

-राजेन्द्र शर्मा-

खड़गवां,26 मई 2026 (घटती-घटना)। महिला एवं बाल विकास विभाग की परियोजना मनेंद्रगढ़ में इन दिनों भारी नाराजगी का माहौल है,लंबे समय से मानदेय भुगतान नहीं होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं आर्थिक संकट से जूझ रही हैं,नाराज कार्यकर्ताओं ने परियोजना अधिकारी को लिखित आवेदन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि यदि जल्द भुगतान नहीं हुआ तो वे शासन के सुपोषण चौपाल कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगी।

बिना वेतन कितना काम करें?- आवेदन में कार्यकर्ताओं ने बताया कि कई महीनों से मानदेय नहीं मिलने के कारण उनके सामने परिवार चलाने तक की समस्या खड़ी हो गई है,रोजमर्रा के खर्च,बच्चों की पढ़ाई और घरेलू जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। इसके बावजूद विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों का लगातार दबाव बनाया जा रहा है, कार्यकर्ताओं का कहना है कि शासन की योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है, लेकिन जब मेहनताना ही समय पर नहीं मिले तो काम करने का उत्साह भी खत्म होने लगता है।

बिजली बिल तक जमा करने में परेशानी- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आवेदन में यह भी उल्लेख किया है कि कई कर्मचारियों के बिजली बिल तक जमा नहीं हो पा रहे हैं, स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि कुछ के घरों की बिजली कटने की नौबत आ चुकी है, व्यंग्य यह है कि एक तरफ सरकार 'सुपोषण' और 'महिला सशक्तिकरण' के बड़े-बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी ओर उन्हीं योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली महिलाएं आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं।

सुपोषण चौपाल के बहिष्कार की चेतावनी- कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने स्पष्ट कहा है कि लगातार उपेक्षा के कारण अब वे आगामी सुपोषण चौपाल कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगी, आवेदन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के हस्ताक्षर शामिल हैं, जिससे साफ है कि मामला व्यापक असंतोष का रूप ले चुका है।

प्रशासन पर उठ रहे सवाल- इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, सरकार जहां महिला एवं बाल विकास योजनाओं को प्राथमिकता देने की बात करती है, वहीं उन्हीं योजनाओं को संचालित करने वाले कर्मचारियों को समय पर मानदेय नहीं मिलना गंभीर लापरवाही माना जा रहा है, यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो इसका सीधा असर विभागीय कार्यक्रमों और सरकारी अभियानों पर पड़ सकता है।

अब देखना होगा कि प्रशासन कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है।

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(3)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदक फरीद खान आ0 स्व0 रज्जब खान, जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपुरा, जयनगर तहसील लटोरी, जिला सूरजपुर, छ0ग0 की ओर से वास्ते मुख्तारआम- इमकान अंसारी पिता शमीम अंसारी, जाति जुलाहा मुसलमान, निवासी इमलीपारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने स्वामित्व की शीट नम्बर -08 मोहल्ला इमलीपारा, नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल भूखण्ड क्रमांक 2967/1, 2972/1, 2972/2 रकबा 0.002, 0.004, 0.012 हे0 कुल रकबा 0.018 हे0 भूमि को रू0 14,00,000/- चौदह लाख रूपये में अनावेदक/ क्रेता मो0 शमीम अंसारी आ0 मोहिउद्दीन अंसारी, सिद्धिका परवीन अंसारी पति समीम अंसारी, जाति जुलाहा, मुसलमान, निवासी इमलीपारा, अम्बिकापुर, जिला सरगुजा, छ0ग0 के पास बिकय करने की अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु मेन्टनेन्स खसरा, शपथ पत्र की छायाप्रति सहित आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उक्त भू-खण्ड के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा-आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 08.06.2026 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत समय-सीमा के बाद प्राप्त दावा-आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा। आज दिनांक 20.05.2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निशातुन निशा आ0 / पति नजमुद्दीन खान जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपुरा चौक महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - न्यू महामाया रोड़, शीट नम्बर - 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2361 / 9 रकबा 756 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/06/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निशातुन निशा आ0 / पति नजमुद्दीन खान जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपुरा चौक महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - न्यू महामाया रोड़, शीट नम्बर - 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2361 / 8 रकबा 736.56 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/06/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी अम्बिकापुर,जिला-सरगुजा,

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

ईश्तहार

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक निशातुन निशा आ0 / पति नजमुद्दीन खान जाति मुसलमान, निवासी मोमिनपुरा चौक महामाया रोड़ अम्बिकापुर, तहसील अम्बिकापुर, जिला सरगुजा छ0ग0 के द्वारा मोहल्ला - न्यू महामाया रोड़, शीट नम्बर - 8 नगर अम्बिकापुर स्थित नजूल प्लाट नम्बर 2361 / 6 रकबा 1447.2 वर्गफीट भूमि का लीज अवधि दिनांक 31.3.2026 को समाप्त हो गई है। जिस कारण लीज अवधि बढ़ाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त के संबंध में यदि किसी व्यक्ति अथवा संस्था को कोई दावा अथवा आपत्ति हो तो अपना लिखित दावा आपत्ति स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक-10/06/2026 तक इस न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेंगा।

आज दिनांक-22/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एंव न्यायालीन पदमुद्रा से जारी ।

सील

नजूल अधिकारी
,अंबिकापुर

न्यायालय नजूल अधिकारी सूरजपुर,जिला-सूरजपुर,छ0ग0

रा.प्र.क्र./अ-20(1)/2025-26

187812893/2

ईश्तहार

आगामी तिथि 19/06/2026

इस सार्वजनिक ईश्तहार के जरिये सर्व साधारण आम जनता / संस्था / विभाग को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है आवेदक प्रदीप कुमार साहू आ0 कन्हैयालाल साहू, उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी वार्ड क्र 06 सेन्ट्रल बैंक गली सूरजपुर थाना व तहसील सूरजपुर जिला-सूरजपुर (छ0ग0) द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अपने स्वामित्व व अधिपत्य की नजूल भूमि प्लाट नम्बर 1878/2829/2 रकबा क्रमशः 4356 वर्गफीट भूमि का लीज दिनांक 31/03/2026 को समाप्त होने से आगामी 30 वर्ष के लिए लीज नवीनीकरण कराये जाने हेतु अनुरोध मा. न्यायालय अपर कलेक्टर सूरजपुर के समक्ष किया गया है। जो अग्रिम कार्यवाही हेतु एतद् न्यायालय को प्राप्त हुआ है। जिसके संबंध में प्रकरण इस न्यायालय में विचाराधीन लंबित है।

अतः इस संबंध में जिस किसी व्यक्ति/संस्था/विभाग को कोई दावा /आपत्ति हो तो वे स्वयं अथवा अपने अभिभाषक / लीगल एजेंट के माध्यम से अपना दावा/आपत्ति दिनांक 19/06/2026 को न्यायालयीन अवधि में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति के संबंध में कोई विचार नहीं किया जायेगा ।

आज दिनांक 15/05/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी किया गया।

सील

नजूल अधिकारी
,सूरजपुर

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,26 मई 2026 (घटती-घटना)। कोरिया जिले के उद्यान विभाग से जुड़ी सोरंगा नर्सरी इन दिनों किसी सरकारी नर्सरी से ज्यादा पारिवारिक फल उत्पादन केंद्र जैसी चर्चा में है, आरोप है कि उद्यान अधीक्षक ने नर्सरी के फलदार वृक्षों की नीलामी में नियमों को किनारे रखकर अपने ही भाई को टेंडर दे दिया। अब सवाल यह उठ रहा है कि यह सरकारी प्रक्रिया थी या घर-घर में विकास योजना? जानकारी के अनुसार नर्सरी में लगे फलदार वृक्षों के फलों की नीलामी की गई थी, लेकिन शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरती गई और अंततः टेंडर अधीक्षक के भाई के नाम पर पहुंच गया, यानी सरकारी आम के पेड़ पर भी रिश्तेदारी का झूला डाल दिया गया।

सोरंगा नर्सरी में भाई-भतीजावाद का 'फलदार' खेल? स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी

आम के पेड़ पर खास रिश्तों की बहार! उद्यान अधीक्षक की कार्यशैली पर उठे गंभीर सवाल

टेंडर प्रक्रिया या पारिवारिक व्यवस्था? सरकारी नर्सरी में अनियमितता के आरोप

भाई को टेंडर, मजदूरों पर बोझ! सोरंगा नर्सरी में नियमों की तुड़ाई का आरोप

नियमों की शाखाओं पर रिश्तेदारी के फल?

जानकार बताते हैं कि किसी भी सरकारी नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और हितों के टकराव से बचना बेहद जरूरी होता है,यदि विभागीय अधिकारी के रिश्तेदार को टेंडर मिलता है तो प्रक्रिया पर स्वतः सवाल खड़े हो जाते हैं, अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या टेंडर प्रक्रिया सार्वजनिक और निष्पक्ष थी? कितने लोगों ने आवेदन किया था? क्या नियमों के अनुसार प्रतिस्पर्धी बोली हुई? क्या वरिष्ठ अधिकारियों को रिश्तेदारी की जानकारी दी गई थी? क्या अधीक्षक ने खुद को प्रक्रिया से अलग किया था? यदि नहीं, तो मामला सिर्फ अनियमितता नहीं बल्कि पद के दुरुपयोग की श्रेणी में भी देखा जा सकता है।

सोरंगा नर्सरी या 'परिवारिक फ्रुट कॉर्पोरेशन'?

स्थानीय लोगों का कहना है कि सोरंगा नर्सरी में मनमानी की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं,लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि जानकारी खुद मजदूरों के माध्यम से बाहर आई है, नाम न छापने की शर्त पर कुछ मजदूरों ने बताया कि फलों की तुड़ाई और रखरखाव का काम उन्हीं से कराया जा रहा है, यानी सरकारी मजदूरी से निजी टेंडर का फायदा पहुंचाने का आरोप सीधे-सीधे विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा कर रहा है, ग्रामीणों में चर्चा है कि यदि गहराई से जांच हो तो नर्सरी में और भी कई अनियमितताएं सामने आ सकती हैं।

'आम' जनता पूछ रही आखिर लाभ किसका?

सरकारी नर्सरी का उद्देश्य आम जनता और विभागीय आय को बढ़ाना होता है,लेकिन यहां स्थिति ऐसी बताई जा रही है कि लाभ का पेड़ कुछ खास लोगों की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि टेंडर प्रक्रिया निष्पक्ष होती तो कई स्थानीय लोग भी भाग ले सकते थे। लेकिन आरोप है कि पूरी प्रक्रिया पहले से सेट थी,लोग तंज कस रहे हैं यहां आम से ज्यादा खास रिश्ते पक रहे हैं।

मजदूरों में नाराजगी,स्थानीय लोगों में आक्रोश

सूत्रों के अनुसार नर्सरी में काम करने वाले कुछ मजदूर भी अंदरखाने नाराज बताए जा रहे हैं,उनका कहना है कि उनसे ऐसा काम कराया जा रहा है जो निजी ठेकेदार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, स्थानीय लोगों का भी आरोप है कि यदि सरकारी संसाधनों का उपयोग निजी लाभ के लिए हो रहा है तो यह सीधे-सीधे सरकारी धन और श्रम का दुरुपयोग है, लोग पूछ रहे हैं कि क्या विभागीय अधिकारियों को यह सब दिखाई नहीं दे रहा? क्या उच्च अधिकारी जांच करेंगे? या फिर मामला फलों की तरह पककर फाइलों में सड़ जाएगा?

भ्रष्टाचार की जड़ें क्या नर्सरी तक पहुंच गईं?

कोरिया जिले में यह मामला अब सिर्फ फलों की नीलामी तक सीमित नहीं रह गया है,यह सरकारी विभागों में बढ़ती रिश्तेदारी संस्कृति और कथित संरक्षणवाद पर भी सवाल खड़ा कर रहा है,व्यंग्य में स्थानीय लोग कह रहे हैं अब सरकारी विभागों में टेंडर नहीं निकलते,परिवार विस्तार योजनाएं निकलती हैं,यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सिर्फ विभागीय अनियमितता नहीं बल्कि प्रशासनिक नैतिकता पर भी गंभीर प्रश्न होगा।

जांच हुई तो खुल सकते हैं कई 'फलदार' राज

सूत्रों का दावा है कि यदि सोरंगा नर्सरी की पूरी जांच हो जाए तो कई और अनियमितताएं सामने आ सकती हैं,इसमें टेंडर प्रक्रिया,मजदूरों के उपयोग, फल बिक्री और विभागीय रिकॉर्ड तक की जांच की मांग उठ रही है, स्थानीय लोगों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यदि नियमों का उल्लंघन हुआ है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई होनी चाहिए।

नाम भाई का...मेहनत मजदूरों की!

मामले में सबसे गंभीर आरोप यह है कि फलों की सुरक्षा,देखरेख और तुड़ाई का काम भी नर्सरी के सरकारी मजदूरों से कराया जा रहा है, यानी टेंडर निजी व्यक्ति के नाम पर और मेहनत सरकारी कर्मचारियों की! यदि यह आरोप सही है तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर टेंडर लेने वाले की जिम्मेदारी कौन निभा रहा है? क्या सरकारी मजदूर अब निजी ठेकेदारों के घरेलू सहायक बन चुके हैं? या फिर विभाग में भाई-भतीजा श्रम समन्वय योजना चलाई जा रही है? स्थानीय लोग व्यंग्य में कह रहे हैं फल सरकारी,पेड़ सरकारी,मजदूर सरकारी...बस मुनाफा निजी!

सबसे बड़ा सवाल...क्या सरकारी पेड़ों पर सिर्फ रिश्तेदारों का हक?

सोरंगा नर्सरी विवाद ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है क्या सरकारी संपत्ति और संसाधन अब सिर्फ प्रभावशाली लोगों के फायदे का जरिया बनते जा रहे हैं? जहां आम जनता नियमों में उलझी रहती है, वहीं कुछ लोगों के लिए वही नियम पेड़ से टूटते पके आम की तरह आसान हो जाते हैं, अब देखना यह होगा कि विभाग इस मामले में जांच करता है या फिर यह मामला भी सरकारी फाइलों के बगीचे में दबकर रह जाएगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं विकास की दो बड़ी मांगें

बायपास सड़क और सिंचाई योजना को लेकर सौंपा मांग पत्र

-संवाददाता-

कोरिया,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम कुशहा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान विष्णु देव साय के समक्ष मोहित राम पैकरा ने जिले के विकास से जुड़ी दो महत्वपूर्ण मांगें रखीं, जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा सौंपे गए मांगपत्र में सड़क और सिंचाई व्यवस्था को लेकर प्रस्ताव शामिल किए गए, जिनकी अब क्षेत्रभर में चर्चा हो रही है।

जमगहना से पोड़ी-बचरा मार्ग तक बायपास सड़क की मांग- मांगपत्र में प्रमुख रूप से जमगहना राष्ट्रीय राज्यमार्ग से डबरीपारा,कसरा, आमापारा और चारपारा होते हुए पोड़ी-बचरा मुख्य मार्ग तक बायपास सड़क निर्माण की मांग की गई है, प्रस्तावित सड़क बनने से क्षेत्र के कई गांव सीधे मुख्य मार्ग से जुड़ जाएंगे,इससे ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और शिक्षा,स्वास्थ्य तथा व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान में कई गांवों के लोगों को मुख्य सड़क तक पहुंचने में लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है, ऐसे में बायपास सड़क क्षेत्र के विकास के लिए अहम साबित हो सकती है।

दुल्हीधार व्यपवर्तन योजना से किसानों को मिलेगा लाभ

जिला पंचायत अध्यक्ष ने दूसरी महत्वपूर्ण मांग दुल्हीधार व्यपवर्तन योजना की स्वीकृति को लेकर रखी,प्रस्तावित योजना के लागू होने से लगभग 850 हेक्टेयर कृषि भूमि सिंचित हो सकेगी,इससे क्षेत्र के किसानों को खेती के लिए पर्याप्त पानी मिल सकेगा और कृषि उत्पादन में वृद्धि होने की संभावना है,किसानों का मानना है कि सिंचाई सुविधा बेहतर होने से फसलों की पैदावार बढ़ेगी और किसानों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, लंबे समय से इस योजना की मांग की जा रही थी।

क्षेत्र में हो रही पहल की सराहना

मुख्यमंत्री के समक्ष इन दोनों मांगों को प्रमुखता से उठाए जाने के बाद स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने मोहित राम पैकरा की पहल की सराहना की है, लोगों का कहना है कि यह मांगें केवल सड़क और सिंचाई तक सीमित नहीं हैं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों के दीर्घकालीन विकास से जुड़ी हुई हैं, अब क्षेत्रवासियों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री स्तर पर मामला पहुंचने के बाद इन योजनाओं को स्वीकृति मिलने की प्रक्रिया तेज होगी और आने वाले समय में क्षेत्र को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

भाजपा के 'ऑडियो वॉर' में कांग्रेस की एंट्री, चरणदास महंत का तंज...रेणुका सिंह को कम से कम डिप्टी सीएम तो बनाइए...

-संवाददाता-

मनेंद्रगढ़/रायपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ भाजपा में कथित वायरल ऑडियो को लेकर चल रहा सियासी घमासान अब और तेज हो गया है,पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया में वायरल ऑडियो को लेकर मचे विवाद में अब कांग्रेस ने भी खुलकर एंट्री कर ली है,नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने भरतपुर-सोनहत विधायक रेणुका सिंह से जुड़े कथित ऑडियो और भाजपा की अंदरूनी राजनीति पर बड़ा बयान देकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। चरणदास महंत ने तंज भरे अंदाज़ में कहा कि वे रेणुका सिंह को धन्यवाद देना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से कहा था कि यदि रेणुका सिंह को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया,तो कम से कम उन्हें उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी जरूर दी जानी चाहिए, महंत ने कहा कि जिस सोच के साथ रेणुका सिंह को दिल्ली से छत्तीसगढ़ की राजनीति में लाया गया, उसी हिसाब से उन्हें महत्व मिलना चाहिए था, दरअसल शनिवार को वायरल हुए पहले कथित ऑडियो में रेणुका सिंह के नाम से यह दावा सामने आया था कि अगली बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और भूपेश बघेल फिर मुख्यमंत्री बनेंगे, इस पर प्रतिक्रिया देते हुए महंत ने मुस्कुराते हुए संतोष जताया, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं,जब महंत से यह पूछा गया कि क्या यह पूरा विवाद रेणुका सिंह की राजनीतिक उपेक्षा और नाराजगी का परिणाम है, क्योंकि 2023 विधानसभा चुनाव के बाद उनका नाम मुख्यमंत्री पद की दौड़ में प्रमुखता से सामने आया था लेकिन बाद में उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं मिली, तब उन्होंने बेहद सधे अंदाज में कहा मैं इस विषय पर इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, प्रदेश में पहले से ही मंत्रिमंडल विस्तार और फेरबदल की चर्चाएं चल रही हैं, ऐसे में भाजपा के भीतर कथित ऑडियो विवाद ने विपक्ष को सरकार को घेरने का नया मुद्दा दे दिया है, हालांकि रेणुका सिंह ने मुंबई से जारी अपने बयान में वायरल दोनों ऑडियो को पूरी तरह फर्जी और एआई जनरेटेड बताया है, उन्होंने इस मामले में सोनहत थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है, फिलहाल कांग्रेस के तंज और भाजपा के भीतर बढ़ती चर्चाओं के बीच यह मामला आने वाले दिनों में प्रदेश की राजनीति को और गर्मा सकता है।

वैधानिक स्पष्टीकरण- वायरल ऑडियो की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, संबंधित पक्षों के बयानों और मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम के आधार पर यह खबर तैयार की गई है।

मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की पहल रंग लाई, सिलफिली मंडी की वर्षों पुरानी समस्या का हुआ समाधान

औचक निरीक्षण के बाद प्रशासन हरकत में...

-संवाददाता-

सूरजपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले की सिलफिली सब्जी मंडी में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को आखिरकार राहत मिल गई है,महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की तत्पर पहल के बाद मंडी परिसर में ट्रांसफार्मर शिफ्टिंग और सार्वजनिक शौचालय संचालन की समस्या का समाधान कर दिया गया है, दरअसल, 10 मई को मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने सिलफिली सब्जी मंडी का औचक निरीक्षण किया था, निरीक्षण के दौरान स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने उन्हें मंडी परिसर में लगे ट्रांसफार्मर की अनुचित स्थिति और सार्वजनिक शौचालय के बंद रहने की समस्या से अवगत कराया था, लोगों ने बताया था कि ट्रांसफार्मर की वजह से मंडी में आवागमन प्रभावित हो रहा है और दुर्घटना का खतरा भी बना रहता है।

ट्रांसफार्मर शिफ्ट होने से बढ़ी सुरक्षा और सुविधा

मंडी परिसर में वर्षों से लगा ट्रांसफार्मर व्यापारियों और ग्राहकों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था। सब्जी खरीदी करने आने वाले लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती थी, वहीं बारिश और भीड़ के दौरान सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती थी, मंत्री राजवाड़े ने मौके पर ही बिजली विभाग के अधिकारियों को समस्या के त्वरित समाधान के निर्देश दिए, इसके बाद विभागीय टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रांसफार्मर को सुरक्षित और उपयुक्त स्थान पर शिफ्ट कर दिया, अब मंडी परिसर में आवागमन पहले की तुलना में अधिक सुगम और सुरक्षित हो गया है, व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसफार्मर हटने से जगह भी खाली हुई है और मंडी में भीड़भाड़ की स्थिति कम हुई है।

सार्वजनिक शौचालय भी हुआ व्यवस्थित

सिर्फ ट्रांसफार्मर ही नहीं, बल्कि मंडी क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय की समस्या का भी समाधान किया गया। लंबे समय से व्यवस्थित संचालन नहीं होने के कारण व्यापारियों, महिलाओं और ग्राहकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था, मंत्री की पहल के बाद शौचालय को नियमित रूप से संचालित कराया गया, जिससे लोगों को स्वच्छ और सुविधाजनक मूलभूत सुविधा उपलब्ध हो सकी है, खासकर महिला व्यापारियों और ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली महिलाओं को इससे राहत मिली है।

स्थानीय लोगों ने जताया आभार

स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों ने मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने शिकायतों को केवल सुनने तक सीमित नहीं रखा,बल्कि मौके पर ही समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित कराई,लोगों का कहना है कि लंबे समय से चली आ रही समस्या का इतने कम समय में समाधान होना प्रशासनिक सक्रियता का उदाहरण है,क्षेत्रवासियों ने उम्मीद जताई कि इसी तरह अन्य जनसमस्याओं का भी त्वरित निराकरण किया जाएगा।

बीमारी से बच गए तो सिस्टम से लड़ो!

कोरिया जिला चिकित्सालय में '10 प्रतिशत चिकित्सा शुल्क' का कथित खेल, स्वास्थ्य व्यवस्था पर सबसे बड़ा सवाल

बीमारी से ज्यादा 'प्रतिशत' का दर्द! कोरिया जिला चिकित्सालय में मेडिकल बिलों पर 10 प्रतिशत कमीशन का कथित खेल

इलाज के बाद शुरू होता है कमीशन उपचार? द्वितीय अभिमत के नाम पर कर्मचारियों से वसूली के आरोप

बीमार कर्मचारी भी नहीं बचे 'कट' संस्कृति से! जिला चिकित्सालय में मेडिकल प्रतिपूर्ति पर बड़ा खेल

मरीज की मजबूरी पर सिस्टम की कमाई! द्वितीय अभिमत बना कथित वसूली का जरिया

इलाज कराकर लौटे कर्मचारी,अब फाइल बचाने की जंग! जिला चिकित्सालय में कमीशनखोरी के आरोप

सरकारी कर्मचारी बोले...इलाज से ज्यादा महंगी पड़ रही प्रक्रिया! कोरिया जिला चिकित्सालय फिर विवादों में

द्वितीय अभिमत बना 'द्वितीय कमाई' का जरिया? इलाज के बाद शासकीय कर्मचारियों की जेब पर दूसरा ऑपरेशन!

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर/कोरिया,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सरगुजा संभाग के स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने के लिए लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं,कभी डॉक्टरों की उपस्थिति जांची जा रही है, कभी मरीजों से बातचीत की जा रही है, तो कभी दवा वितरण व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए जा रहे हैं, सरकार मंचों से बेहतर स्वास्थ्य सेवा और जनहित का भाषण दे रही है, लेकिन उसी सरगुजा संभाग के कोरिया जिला चिकित्सालय से जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, उसने स्वास्थ्य व्यवस्था की नसों में दौड़ रहे कथित प्रतिशत तंत्र को उजागर कर दिया है, आरोप है कि यहां इलाज कराकर लौटे शासकीय कर्मचारियों से मेडिकल प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक द्वितीय अभिमत जारी करने के नाम पर खुलेआम 10 प्रतिशत कमीशन मांगा जा रहा है, यानी बीमारी से परेशान कर्मचारी को अब इलाज से ज्यादा फाइल की बीमारी डराने लगी है, व्यंग्य में कर्मचारी कह रहे हैं यहां इलाज मुफ्त नहीं, प्रतिशत आधारित हो चुका है।

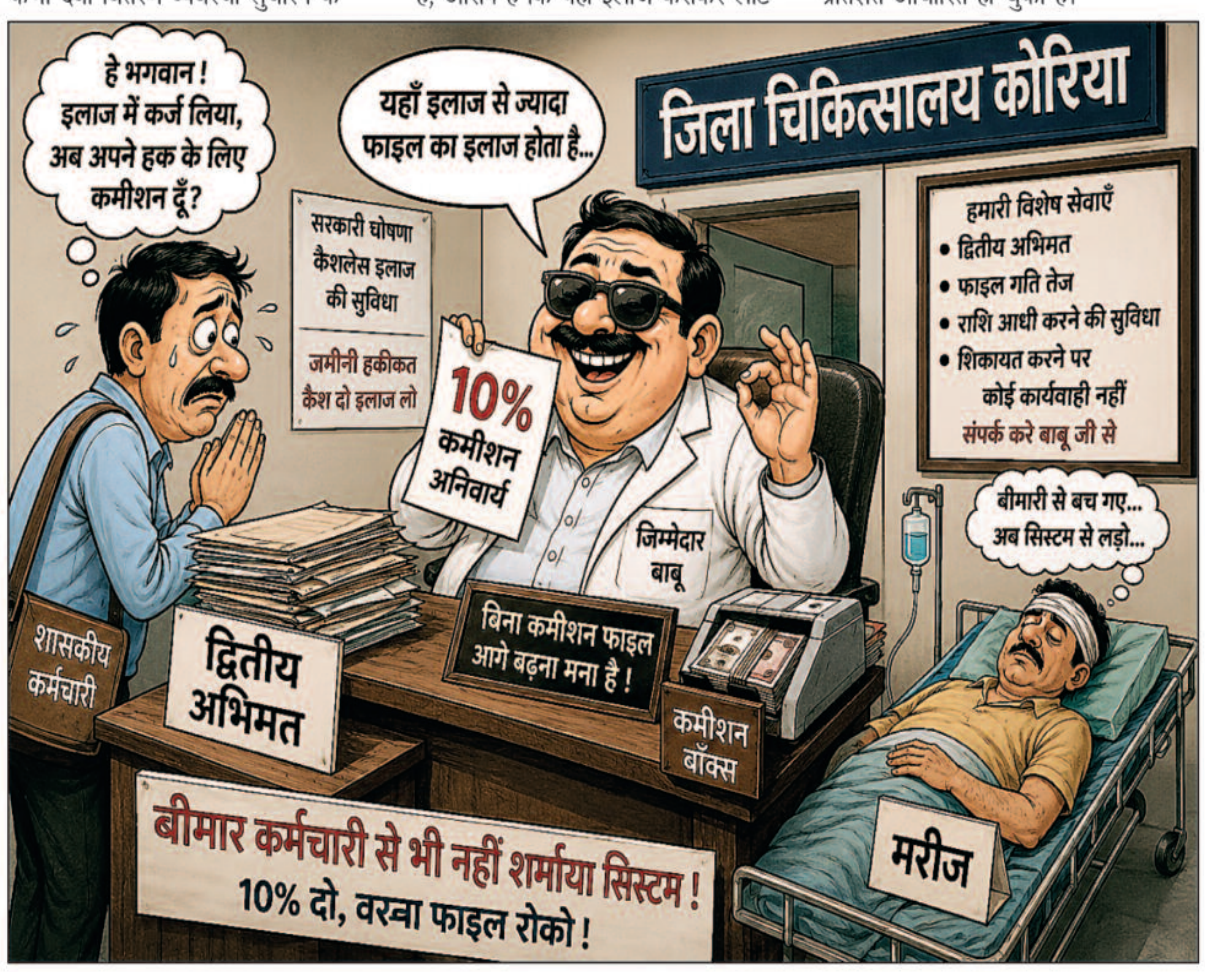

इलाज खत्म,अब शुरू होता है 'फाइल उपचार'

सरकारी कर्मचारी जब खुद का या अपने परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराकर लौटता है, तब तक वह मानसिक,शारीरिक और आर्थिक रूप से पहले ही टूट चुका होता है,किसी ने जमीन गिरवी रखी, किसी ने रिश्तेदारों से उधार लिया,तो किसी ने वर्षों की जमा पूंजी इलाज में लगा दी,लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति का दावा लेकर सरकारी दफ्तरों की चौखट पर पहुंचता है,नियमों के अनुसार कई मामलों में कर्मचारी को जिला चिकित्सालय से द्वितीय अभिमत लेना पड़ता है,यही वह जगह है जहां कथित तौर पर प्रतिशत मॉडल सक्रिय हो जाता है,कर्मचारियों का आरोप है कि जैसे ही वे फाइल लेकर जिला चिकित्सालय पहुंचते हैं,उन्हें सीधे तौर पर समझा दिया जाता है 10 प्रतिशत दीजिएज तभी फाइल आगे बढ़ेगी,यदि कर्मचारी सवाल पूछे तो कथित तौर पर उसे यह भी बताया जाता है कि कमीशन नहीं देने पर या तो द्वितीय अभिमत नहीं मिलेगा या फिर मेडिकल बिल की राशि कम कर दी जाएगी, यानी बीमारी से लड़कर लौटा कर्मचारी अब व्यवस्था की नई बीमारी से लड़ने को मजबूर है।

द्वितीय अभिमत या 'द्वितीय कमाई केंद्र'?

सरकार ने द्वितीय अभिमत की व्यवस्था इसलिए बनाई थी ताकि चिकित्सा प्रतिपूर्ति में पारदर्शिता बनी रहे और फर्जी दावों पर रोक लग सके, लेकिन कर्मचारियों का आरोप है कि जिला चिकित्सालय में यही प्रक्रिया कथित तौर पर कमाई की स्थायी खिड़की में बदल चुकी है, कर्मचारियों का कहना है कि यहां फाइलें नियमों से कम और समझदारी से ज्यादा चलती हैं,व्यंग्य में एक कर्मचारी ने कहा यहां बीमारी का इलाज डॉक्टर करते हैं और फाइल का इलाज प्रतिशत करता है, कुछ कर्मचारी तो इसे द्वितीय अभिमत सेवा शुल्क तक कहने लगे हैं।

बीमार कर्मचारी की जेब पर दूसरा ऑपरेशन

इस पूरे मामले का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि कर्मचारी इलाज के बाद फिर कर्ज लेने को मजबूर हो रहा है इस बार दवा खरीदने के लिए नहीं,बल्कि अपने ही अधिकार की फाइल बचाने के लिए,कर्मचारियों का कहना है कि मेडिकल प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया वैसे ही वर्षों तक लटकी रहती है,कई मामलों में भुगतान होने में सालों लग जाते हैं,ऐसे में कर्मचारी डर के कारण कथित कमीशन दे देता है ताकि कम से कम उम्मीद बनी रहे कि उसका पैसा वापस मिल सकेगा,यानी यहां कर्मचारी दो बार टूट रहा है पहली बार बीमारी से और दूसरी बार व्यवस्था से।

सब ऊपर तक सेट है,कथित दावा और बढ़ी गंभीरता

सबसे गंभीर आरोप यह है कि कथित कमीशन मांगने वाले कर्मचारी खुले तौर पर दावा करते हैं कि शिकायत करने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि सब ऊपर तक तय है,यदि यह आरोप सच हैं तो मामला सिर्फ व्यक्तिगत भ्रष्टाचार का नहीं, बल्कि पूरी प्रशासनिक कार्यप्रणाली की सड़ चुकी मानसिकता का संकेत है, लोग तंज कस रहे हैं यहां फाइल की स्पीड इंटरनेट से नहीं,प्रतिशत से बढ़ती है।

सबसे बड़ा सवाल...क्या अब इलाज भी 'प्रतिशत' पर चलेगा?

कोरिया जिला चिकित्सालय पर लगे ये आरोप सिर्फ एक अस्पताल की कहानी नहीं हैं,यह उस व्यवस्था का आईना हैं जहां बीमारी, मजबूरी और सरकारी प्रक्रिया भी कथित कमाई का जरिया बनती जा रही है, एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री अस्पतालों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं,दूसरी तरफ उन्हीं के संभाग में कर्मचारी अपने ही अधिकार के लिए कथित कट देने को मजबूर बताए जा रहे हैं, अब देखना यह होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस मामले में गंभीर कार्रवाई करता है या फिर द्वितीय अभिमत का यह कथित खेल यूं ही चलता रहेगा और बीमार कर्मचारी इलाज से ज्यादा व्यवस्था से डरता रहेगा।

सरगुजा संभाग में मंत्री सक्रिय,नीचे सिस्टम 'सक्रिय कमाई' में?

स्वास्थ्य मंत्री लगातार अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं,मरीजों को बेहतर सुविधा देने की बात हो रही है,लेकिन जिला स्तर पर सामने आ रही शिकायतें एक अलग ही कहानी बयां कर रही हैं,अब लोगों के बीच चर्चा है कि क्या कुछ अधिकारी-कर्मचारी स्वास्थ्य मंत्री की छवि खराब करने में लगे हैं? क्या उनकी सरल और सहज कार्यशैली को कमजोरी समझ लिया गया है? क्या नीचे बैठे जिम्मेदार लोग सुधार की कोशिशों को अंदर ही अंदर खोखला कर रहे हैं? क्योंकि यदि मंत्री सक्रिय हैं और फिर भी भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आ रही हैं,तो इसका मतलब कहीं न कहीं व्यवस्था पर पकड़ कमजोर है।

कैशलेस इलाज की घोषणा और जमीन पर 'कैश दो' मॉडल

सरकार ने बजट में कर्मचारियों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा लागू करने की बात कही थी ताकि इलाज के दौरान आर्थिक बोझ कम हो सके, लेकिन जमीनी स्थिति देखकर कर्मचारी व्यंग्य में कह रहे हैं यहां कैशलेस इलाज नहीं, कैश देकर इलाज वाली फाइल चलती है, एक कर्मचारी ने कटाक्ष करते हुए कहा अगर व्यवस्था नहीं बदली तो भविष्य में मृत्यु प्रमाण पत्र पर भी प्रतिशत तय हो जाएगा।

बीमार कर्मचारी भी बन गया 'कमाई का अवसर'

कर्मचारियों का कहना है कि कोई भी कर्मचारी मेडिकल प्रतिपूर्ति के जरिए अमीर बनने नहीं आता,वह सिर्फ अपने इलाज में खर्च हुई राशि वापस चाहता है, जो उसका वैधानिक अधिकार है, लेकिन यदि उसी अधिकार पर कथित कमीशन की परत चढ़ जाए तो यह सिर्फ भ्रष्टाचार नहीं, बल्कि संवेदनहीनता का सबसे कुरूप चेहरा है,यह मामला केवल पैसों का नहीं, बल्कि उस मानसिकता का है जहां बीमार और परेशान व्यक्ति को भी कमाई का अवसर समझा जा रहा है।

जिला चिकित्सालय की छवि पर गंभीर सवाल

कोरिया जिला चिकित्सालय पहले भी कई विवादों को लेकर चर्चा में रहा है, लेकिन इस बार मामला इसलिए ज्यादा गंभीर माना जा रहा है क्योंकि इसमें सीधे तौर पर शासकीय कर्मचारियों के अधिकार और आर्थिक संकट का प्रश्न जुड़ा हुआ है,लोगों का कहना है कि अस्पताल वह जगह होती है जहां मरीज राहत की उम्मीद लेकर जाता है,लेकिन यदि वहीं उसे प्रतिशत और कमीशन का सामना करना पड़े तो व्यवस्था पर भरोसा कैसे बचेगा? एक स्थानीय नागरिक ने व्यंग्य में कहा यहां IC में मरीज कम और फाइलें ज्यादा भर्ती हैं।

कर्मचारियों में आक्रोश,जांच की मांग तेज

अब कर्मचारियों द्वारा पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठ रही है, उनकी मांग है कि द्वितीय अभिमत प्रक्रिया ऑनलाइन की जाए, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम लागू हो,कथित वसूली की स्वतंत्र जांच हो,दोषियों पर कार्रवाई हो,मेडिकल प्रतिपूर्ति प्रक्रिया समयबद्ध बनाई जाए, शिकायतकर्ताओं की पहचान सुरक्षित रखी जाए, कर्मचारियों का कहना है कि यदि समय रहते इस कथित खेल पर रोक नहीं लगी तो सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा पूरी तरह खत्म हो जाएगा।

सूरजपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी और होम्योपैथी से मरीजों को मिली राहत

बीपी,शुगर जांच से लेकर हड्डी और नसों के उपचार तक,बड़ी संख्या में पहुंचे लोग

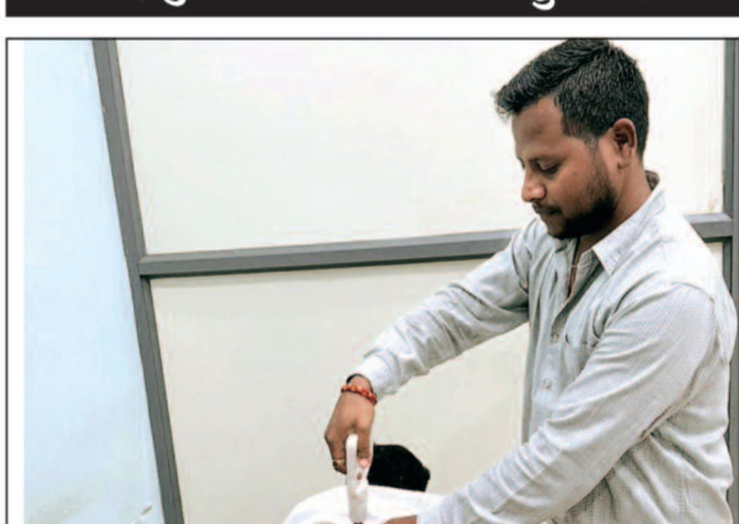

-संवाददाता-

सूरजपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और आमजन को निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सूरजपुर में रविवार को निःशुल्क स्वास्थ्य परामर्श एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, श्याम आयुर्वेदिक वेलनेस एवं फिजियोथेरेपी सेंटर द्वारा आयोजित इस शिविर में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चले इस स्वास्थ्य शिविर में लोगों के लिए निःशुल्क बीपी जांच,शुगर जांच और स्वास्थ्य परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई गई,शिविर में आयुर्वेदिक,होम्योपैथिक,फिजियोथेरेपी एवं ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच कर उन्हें उचित उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सलाह दी गई।

शिविर में मुख्य रूप से हड्डी, जोड़ और नसों से संबंधित समस्याओं से पीड़ित मरीजों की जांच की गई, चिकित्सकों ने बिना ऑपरेशन उपचार पद्धति के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी, आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भी बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे और विशेषज्ञों से परामर्श लिया, शिविर में प्रमुख रूप से डॉ. पी.एम. त्रिपाठी (हड्डी रोग विशेषज्ञ),डॉ. प्रदीप देवांगन (आयुर्वेदिक चिकित्सक), डॉ. सोनाली कुण्डू (फिजियोथेरेपिस्ट) एवं डॉ. विजय यादव (होम्योपैथी चिकित्सक) उपस्थित रहे। वहीं आयोजन की जिम्मेदारी श्याम आयुर्वेदिक वेलनेस एवं फिजियोथेरेपी सेंटर के प्रबंधक हिमांशु जैन द्वारा संभाली गई, डॉ. सोनाली कुण्डू ने कई मरीजों का फिजियोथेरेपी के माध्यम से उपचार किया और लोगों को नियमित व्यायाम एवं सही बॉडी पोस्टर के महत्व के बारे में बताया, वहीं डॉ. प्रदीप देवांगन ने पंचकर्म और अग्निकर्म थेरेपी के माध्यम से मरीजों का उपचार करते हुए आयुर्वेदिक जीवनशैली अपनाने की सलाह दी, मुख्य चिकित्सक डॉ. पी.एम. त्रिपाठी ने कहा कि यदि लंबे समय तक स्वस्थ रहना है तो लोगों को आधुनिक चिकित्सा के साथ-साथ फिजियोथेरेपी और आयुर्वेद को भी अपनी जीवनशैली का हिस्सा बनाना होगा, उन्होंने कहा कि नियमित व्यायाम, प्राणायाम और संतुलित आहार कई गंभीर बीमारियों से बचाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, शिविर में उपस्थित चिकित्सकों ने लोगों को समय-समय पर स्वास्थ्य जांच कराने, तनाव मुक्त जीवन जीने और बेहतर दिनचर्या अपनाने के लिए भी प्रेरित किया, शिविर के सफल आयोजन पर स्थानीय लोगों ने आयोजकों की सराहना करते हुए इसे जनहित में सराहनीय पहल बताया।

मृतक का बना दिया वारिस,फर्जी दस्तावेजों से 3.25 हेक्टेयर जमीन हड़पने का खुलासा

फर्जी नामांतरण कर मुआवजा और नौकरी पाने की थी तैयारी, चंदौरा पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार

-संवाददाता-

सूरजपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। सूरजपुर जिले में फर्जी दस्तावेजों के जरिए जमीन हड़पने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, थाना चंदौरा पुलिस ने धोखाधड़ी और फर्जी नामांतरण कर जमीन अपने नाम कराने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है,आरोप है कि मृत व्यक्ति का फर्जी उत्तराधिकारी बनाकर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया गया और इसके जरिए मुआवजा व नौकरी प्राप्त करने की तैयारी की जा रही थी।

ग्राम परमेश्वरपुर निवासी 75 वर्षीय शिवचरण ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सूरजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि ग्राम बंशीपुर उप तहसील जरही स्थित उनकी भूमि को फर्जी तरीके से दूसरे लोगों के नाम दर्ज करा लिया गया है, शिकायत में खसरा नंबर 273, 290, 1584, 1653, 1654, 1673, 1675 और 1676 की कुल 3.25 हेक्टेयर भूमि का उल्लेख किया गया था, मामले की जांच एसडीओपी प्रतापपुर द्वारा की गई, जांच में सामने आया कि आरोपी पक्ष ने मृतक शिवभजन का फर्जी उत्तराधिकारी बनाकर नामांतरण प्रक्रिया पूरी कराई थी।

मृत्यु के दो साल बाद हुआ नामांतरण

जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि शिवभजन की मृत्यु 20 सितंबर 2014 को हो चुकी थी,लेकिन वर्ष 2016 में फर्जी पंचनामा तैयार कर लक्ष्मण सिंह को उसका पुत्र और वैध उत्तराधिकारी दर्शा दिया गया, इसके बाद राजस्व रिकॉर्ड में फौती नामांतरण कर भूमि को अपने नाम दर्ज करा लिया गया,पुलिस के अनुसार यह पूरा काम सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी, छल और जालसाजी के माध्यम से किया गया था,आरोपियों का उद्देश्य जमीन के साथ-साथ मुआवजा और नौकरी का लाभ लेना भी बताया गया है।

आरोपी गिरफ्तार,एक अन्य की तलाश जारी

मामले में पुलिस ने आरोपी अशोक सिंह को गिरफ्तार कर लिया है,पूछताछ में उसने फर्जी पंचनामा तैयार कर भूमि अपने पिता के नाम नामांतरित कराने की बात स्वीकार की है, मामले में एक अन्य आरोपी की तलाश अभी जारी है, पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 419, 420, 467, 468, 471, 120(बी) और 34 के तहत अपराध दर्ज किया है।

एसएसपी के निर्देश पर हुई कार्रवाई

प्रशांत कुमार ठाकुर के निर्देश पर थाना चंदौरा पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया,इस कार्रवाई में थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह धुर्वे,एएसआई नील कुसुम बेक,आरक्षक अवधेश कुशवाहा,शेखर मानिकपुरी और अमृत जगत की महत्वपूर्ण भूमिका रही,फिलहाल पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी हुई है।

सुनील दत्त की 21 वीं डेथ एनिवर्सरी पर संजय दत्त का इमोशनल पोस्ट आप जैसा पिता पाकर...

वेटरन एक्टर रहे सुनील दत्त की आज 21वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जा रही है और इस मौके पर संजय दत्त का पोस्ट सामने आया है।सुनील दत्त हिंदी सिनेमा के वो कलाकार थे, जिन्होंने लंबे समय तक बड़े पर्दे पर राज किया था। एक दमदार अभिनेता के तौर पर फैंस के दिलों पर राज करने वाले सुनील साहब का निधन 21 साल पहले आज ही के दिन हुआ था। सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी के मौके पर अभिनेता संजय दत्त ने अपने पिता को याद किया है और हर बार की तरह इस बार भी एक भावुक पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिसमें सुनील और संजय की कुछ अनसीन तस्वीरें शामिल हैं, आइए एक नजर संजू बाबा के इस पोस्ट पर डाली जाए।

सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर संजय दत्त का पोस्ट

संजय दत्त अपने माता-पिता के बेहद करीब रहे। अक्सर देखा जाता है कि वह सोशल मीडिया पर अपने पिता सुनील दत्त और मां नरगिस को याद करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में पता सुनील के डेथ एनिवर्सरी के मौके पर उनकी तरफ एक पोस्ट आना बनता है।
25 मई मंगलवार को संजय दत्त ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट पोस्ट शेयर किया है, जिसमें संजय और सुनील की कई अनसीन तस्वीरें शामिल हैं। इस ट्वीट के कैप्शन में संजय ने लिखा है-पापा,मुझे हमेशा आपकी याद आती है और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं। आप मेरी जिंदगी का एक मजबूत सहारा थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आप जैसा पिता पाकर मैं खुद को सम्मानित और आभारी महसूस करता हूं। इस तरह सुनील दत्त की डेथ एनिवर्सरी पर संजय ने उन्हें दिल से याद किया है। बता दें कि 25 मई 2005 को हार्ट अटैक की वजह से सुनील साहब का निधन हुआ था। एक सफल अभिनेता होने के अलावा वह कद्दावर राजनेता भी रहे थे।

संजय दत्त की अपकमिंग मूवीज

इसके अलावा बात की जाए संजय दत्त के वर्क फ्रंट के बारे में तो धुरंधर फ्रेंचाइजी की सफलता के बाद संजय की अपकमिंग फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी हो गई है। जिनमें मल्टी स्टारर कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल का नाम शामिल है। इसके अलावा संजय की बहुचर्चित फिल्म खलनायक का पार्ट 2 हाल ही में अनाउंस हुआ है, जिसका निर्देशन सुभाष घई करने वाले हैं। इसके अलावा अन्य कई मूवीज में संजय की झलक देखने को मिलेगी।

राजीव वर्मा ने क्यों मोड़ा बॉलीवुड से मुंह?

अमिताभ बच्चन से एक्टर का है खास रिश्ता

सलमान खान और अजय देवगन के ऑन स्क्रीन पिता बने राजीव वर्मा बॉलीवुड का एक जाना-पहचाना चेहरा थे? अब वे क्या है और क्या करते हैं राजीव वर्मा, जो बॉलीवुड में पिता की भूमिकाओं के लिए मशहूर हैं, अक्सर सलमान खान के ऑन-स्क्रीन पिता का किरदार निभाते रहे हैं। लेकिन एक बेहतरीन एक्टर होने के बावजूद उन्होंने इंडस्ट्री क्यों छोड़ी और अब वे क्या कर रहे हैं आइए जानते हैं।

ऑनस्क्रीन पिता के रूप में थे मशहूर

राजीव वर्मा ने फिल्म मैंने प्यार किया में सलमान खान के पिता का किरदार निभाया वहीं हम दिल दे चुके सनम में अजय देवगन के पिता का। वेटरन एक्टर ने खुद इस बात का खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्होंने धीरे-धीरे मेनस्ट्रीम बॉलीवुड और टेलीविजन से दूरी बना ली, जबकि वे पर्दे पर पिता की भूमिका निभाने वाले सबसे ज्यादा पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक थे।

राजीव ने क्यों छोड़ी एक्टिंग

एक इंटरव्यू में राजीव ने बताया था कि सालों तक एक ही तरह की कास्टिंग और रूटीन काम करते-करते,आखिरकार उनका इस इंडस्ट्री से मन उठ गया। रेगुलर एक्टिंग असाइनमेंट छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बात करते

हुए,राजीव ने कहा,धीरे-धीरे मजा आना बंद हो गया था। बस रूटीन काम था कि यार चलना है मुंबई में है तो करें,यहीं करते रहें। अभिनेता ने खुलासा किया कि काम से पूरी तरह दूर होने से कई साल पहले ही उन्हें खुद को काम से अलग महसूस होने लगा था। उन्होंने साझा किया, मुझे लगने लगा था कि यार अब मैं चलता हूं, अब मन नहीं करता। मजा नहीं आ रहा है मुझे। वैसे भी कोई जरूरी नहीं थी। होटल मेरा एक छोटा सा है यहां, वो चलता है, दाल रोटी है, खुश हैं।

पर्सनल टाइम हो गई थी कमी

राजीव ने कहा कि दशकों तक लगातार काम करने के बाद, वह परिवार और दोस्तों के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। उन्होंने कहा, %यार दोस्तों से मिलना, शादी ब्याह में जाना, रिश्तेदारों से मिलना, परिवार के साथ वक्त गुजारना... ये सब लगभग नगण्य हो गया था।

इंडस्ट्री में टाइपकास्ट होने पर की बात

राजीव ने यह भी बताया कि कैसे बॉलीवुड अक्सर उनके पहले प्रदर्शन की सफलता के बाद उन्हें समान भूमिकाओं में टाइपकास्ट करता है। उन्होंने बताया,एक तरह का किरदार आपने कर लिया तो फिर जो बनाने वाले हैं वो ज्यादा नहीं सोचते। वो सोचते हैं पिता के रोल में कौन चल रहा है? और फिर आप कैटेगरी में फिक्स हो जाते हैं।

पिता का किरदार निभाते हुए थक गए थे एक्टर

अभिनेता ने कहा कि मैंने प्यार किया के ब्लॉकबस्टर होने के बाद निर्माता बार-बार उन्हीं अमीर व्यवसायी या पिता की भूमिकाओं के लिए उनके पास आए। उन्होंने याद करते हुए कहा,हर फिल्म में वही मिलता था। मैंने पूछा किरदार क्या है? तो कहते थे,सर वही जो आपने किया था। तो मैंने कहा मैं छोड़ देता हूं, मुझे मजा नहीं आ रहा था। थिएटर का आदमी था।

अब क्या करते हैं राजीव?

राजीव वर्मा का कहना है कि थिएटर अब उनका असली जुनून है आज राजीव थिएटर से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं और भोपाल में अपना थिएटर ग्रुप चलाते हैं। वह नाटक भी सिखाते हैं और कार्यशालाएं भी संचालित करते हैं।

अमिताभ बच्चन और जया बच्चन से रिश्ता

राजीव वर्मा की शादी जया बच्चन की बहन रीता से हुई। इसके उनका रिश्ता बच्चन परिवार से जुड़ा हुआ है। यानी वे जया बच्चन के ब्रदर इन लॉ हैं।

दो फिल्में मिलाकर डेविड धवन ने बना दी थी गोविंदा की मूवी

मशहूर निर्देशक डेविड धवन ने दो पुरानी फिल्मों को मिलाकर गोविंदा की एक कल्ट मूवी का निर्माण किया था। सिनेमा जगत के निर्देशक और एक्टर की फेमस जोड़ी के बारे में जिक्र किया जाए तो उसमें डेविड धवन और गोविंदा का नाम जरूर शामिल होगा। मौजूदा समय में बतौर निर्देशक अपने करियर की आखिरी फिल्म है जवानी तो इश्क होना है को लेकर डेविड का नाम चर्चा में बना हुआ है। इस बीच हम आपको उनकी और गोविंदा की एक ऐसी कल्ट मूवी के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी कहानी 90 के दशक की दो बड़ी हिट फिल्मों से मेल खाती थी।

गोविंदा की क्लट फिल्म

साल 1989 में आई फिल्म ताकतवर से गोविंदा ने डायरेक्टर डेविड धवन की फिल्मों में काम करना शुरू किया और इसके बाद इन दोनों की जोड़ी कुछ ऐसी जमी की 90 के दशक में दोनों ने एक साथ कई सफल मूवीज दीं। उनमें से एक फिल्म थी शोला और शबनम, जिसे 1992 में सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इस मूवी में गोविंदा अभिनेत्री दिव्या भारती के साथ नजर आए थे। शोला और शबनम बॉक्स ऑफिस पर कमर्शियल तौर पर सफल रही और सुपरहिट साबित हुई है। मूवी की कहानी और गानों ने फैंस का दिल जीता था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि निर्देशक डेविड धवन की शोला और शबनम की कहानी उसी दौर की दो पुरानी फिल्में आमिर खान की दिल और सनी देओल की घायल से मिलती है।
शोला और शबनम के पहले हाफ में दिल फिल्म की तरह रोमांस और कॉमेडी देखने को मिलती है, जबकि इंटरवल के बाद गोविंदा की मूवी का टोन ही चेंज हो जाता है और ये एक्शन थ्रिलर के तौर पर सामने आती है, जो सनी देओल की घायल से मेल खाती है। इस तरह से इन दोनों मूवीज को मिलाकर देखा जाए तो शोला और शबनम निकलकर सामने आती है।

15 से ज्यादा मूवीज में दिखी गोविंदा और डेविड की जोड़ी

गोविंदा ने अपने एक्टिंग करियर की सबसे ज्यादा हिट फिल्में डेविड धवन के डायरेक्शन में दी हैं, 15 से अधिक फिल्मों में दोनों की जोड़ी एक साथ आई।

प्रिंस चौधरी ने तान्या मित्तल पर लगाए गंभीर आरोप

देशी ब्रांड आउटफिट विवाद से बढ़ा विवाद

प्रिंस चौधरी नाम के एक इन्फ्लुएंसर,जो नायाब बाय प्रिंस नाम के एक देसी ब्रांड के मालिक हैं,ने तान्या मित्तल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिंस ने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें तान्या और उनकी टीम पर कथित तौर पर उनके लेबल से एक ड्रेस वापस न करने का आरोप लगाया गया है। यह बताते हुए कि उन्होंने पब्लिकली बोलने का फैसला क्यों किया,प्रिंस ने कहा,हाल ही में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में मैं पब्लिकली बात नहीं करना चाहता था लेकिन 4 महीने हो गए हैं और मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है।÷ प्रिंस ने आगे बताया कि उन्होंने अपने ब्रांड नायाब बाय प्रिंस के साथ कोलेबोरेशन के लिए पर्सनली वॉट्सऐप पर तान्या से कॉन्टैक्ट किया था। उनके मुताबिक, तान्या ने पॉजिटिव जवाब दिया और उनसे कहा कि जब कोई पर्सनली उनसे कॉन्टैक्ट करता है तो वह आमतौर पर मना नहीं करती हैं। फिर उन्होंने कथित तौर पर अपने स्टाइलिस्ट का नंबर उनके साथ शेयर किया। प्रिंस ने दावा किया कि स्टाइलिस्ट ने उनके कलेक्शन से तीन आउटफिट शॉर्टलिस्ट किए। फिर उन्होंने चुने हुए आउटफिट में से एक नोएडा में तान्या को भेजा और टीम को बताया कि उन्हें एक महीने के अंदर ड्रेस वापस चाहिए होगी। हालांकि, तय समय बीत जाने के बाद, प्रिंस ने दावा किया कि उन्होंने आउटफिट के बारे में फॉलो-अप करना शुरू कर दिया है। उस सिचुएशन को याद करते हुए उन्होंने कहा, तभी पूरी बात बदल गई। प्रिंस के मुताबिक, तान्या के स्टाइलिस्ट ने बाद में उन्हें बताया कि तान्या मंदिर जाते समय यह आउटफिट दोबारा पहनेंगी। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि कुछ समय बाद, जवाब पूरी तरह से बंद हो गए। प्रिंस ने फिर दावा किया कि स्टाइलिस्ट ने टीम के एक और मेंबर का कॉन्टैक्ट शेयर किया और उनसे उस व्यक्ति के साथ आगे कोऑर्डिनेट करने के लिए कहा। प्रिंस ने आरोप लगाया कि हालांकि तान्या की टीम ने उन्हें कई बार भरोसा दिलाया कि आउटफिट वापस कर दिया जाएगा, फिर भी उन्हें वह नहीं मिला। अपनी निराशा जताते हुए उन्होंने कहा, 4 महीने हो चुके हैं, आज भी मुझे कोई आउटफिट नहीं मिला है।

जान्हवी कपूर ने बनारसी टेक्सटाइल को दिया मॉडर्न कॉउचर टच

पारंपरिक बुनाई एक बार फिर फैशन की दुनिया में चर्चा का केंद्र बन रही है और इस ट्रेंड को नई पहचान देने में बॉलीवुड एक्ट्रेस जान्हवी कपूर का नाम सामने आ रहा है। हाल ही में जान्हवी कपूर ने बनारसी टेक्सटाइल को एक आधुनिक कॉउचर लुक में पेश किया, जिसने फैशन प्रेमियों का

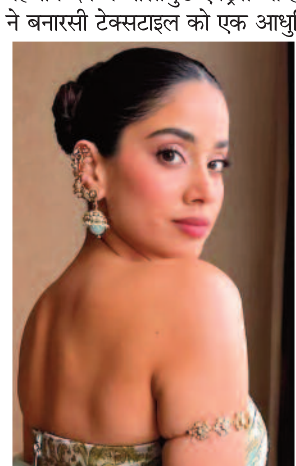

ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। जान्हवी कपूर इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'पेड्डी' के प्रमोशन में व्यस्त हैं और इस दौरान वे लगातार एथनिक लुक्स में नजर आ रही हैं। उनके हर आउटफिट में भारतीय परंपरा और आधुनिक फैशन का अनोखा मेल देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में उनका हालिया बनारसी आउटफिट सोशल मीडिया पर खास चर्चा में है। बनारसी कपड़े भारत की पारंपरिक बुनाई कला का प्रतीक माने जाते हैं, जिन्हें खासतौर पर उनकी बारीक कारीगरी, चमकदार डिजाइन और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है। जान्हवी कपूर ने इसी पारंपरिक फैब्रिक को एक नए और मॉडर्न अंदाज में पेश किया, जिससे यह और भी स्टाइलिश और ग्लैमरस नजर आया। उनका यह लुक पारंपरिक बनारसी फैब्रिक को कॉउचर डिजाइन के साथ जोड़कर तैयार किया गया था, जिसमें आधुनिक सिल्हूट और क्लासिक बनारसी बुनाई का खूबसूरत संतुलन देखने को मिला। इस स्टाइल ने न केवल उनकी फैशन सेंस को उजागर किया, बल्कि भारतीय टेक्सटाइल की खूबसूरती को भी एक नया मंच दिया। फैशन विशेषज्ञों का मानना है कि जान्हवी कपूर जैसे युवा सितारे जब पारंपरिक कपड़ों को आधुनिक अंदाज में प्रस्तुत करते हैं, तो इससे भारतीय हैंडलूम और बुनाई को नई पीढ़ी के बीच भी लोकप्रियता मिलती है। यह ट्रेंड न केवल फैशन इंडस्ट्री में बदलाव लाता है, बल्कि पारंपरिक कारीगरों को भी नई पहचान दिलाने में मदद करता है। जान्हवी कपूर का यह लुक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, और फैंस उनके इस एथनिक अवतार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि उन्होंने बनारसी टेक्सटाइल को एक ग्लोबल फैशन स्टेटमेंट में बदल दिया है।

खेल समाचार

भारत के खिलाफ टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान की टीम का ऐलान

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारत के खिलाफ होने वाले एक टेस्ट और वनडे सीरीज के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है...दोनों ही टीमों की कप्तानी हशमतुल्लाह शाहिदी को सौंपी गई है...

नई दिल्ली,26 मई 2026। भारतीय सरजमीं पर होने वाली आगामी क्रिकेट सीरीज के लिए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी वनडे और टेस्ट टीम की घोषणा कर दी है। दोनों ही फॉर्मेट में टीम की कमान बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज हशमतुल्लाह शाहिदी को सौंपी गई है। अफगानिस्तान का यह भारत दौरा 6 जून से शुरू होकर 20 जून तक चलेगा जिसके तहत दोनों टीमों के बीच एक एकमात्र ऐतिहासिक टेस्ट मैच और तीन मैचों की रोमांचक वनडे सीरीज खेली जाएगी।

वनडे और टेस्ट टीम का ऐलान

अफगानिस्तान ने इस महत्वपूर्ण दौरे के लिए अपनी टीम में अनुभव और युवा जोश का बेहतरीन संतुलन बनाने की कोशिश की है। वनडे सीरीज के लिए अफगानिस्तान ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। वनडे स्क्वॉड में जादुई स्पिनर राशिद खान, विस्फोटक बल्लेबाज रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान जैसे स्टार खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का पासा पलटने का माद्दा रखते हैं।

टेस्ट टीम में नए चेहरों पर भरोसा

वहीं,एकमात्र टेस्ट मैच के लिए अफगानिस्तान ने अपनी टीम में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। टेस्ट टीम के बल्लेबाजी क्रम को मजबूती देने का जिम्मा रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज और ऑलराउंडर अजमतुल्लाह उमरजई के कंधों पर होगा। विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी के लिए इस बार अफसर जजई और इकराम अलीखिल दोनों को टेस्ट टीम में जगह दी गई है।

स्पिन और गेंदबाजी आक्रमण का नया चक्रव्यूह

भारत की स्पिन-अनुकूल पिचों को ध्यान में रखते हुए अफगानिस्तान ने अपने स्पिन विभाग को काफी धारदार बनाया है। टेस्ट फॉर्मेट में टीम का स्पिन आक्रमण मुख्य रूप से शराफुद्दीन अशरफ और कैस अहमद की जोड़ी पर निर्भर करेगा। इसके अलावा, तेज गेंदबाजी और स्पिन के बैकअप के तौर पर नांग्याल खारोताई, जिया यू रहमान शरीफी और बिलाल सामी जैसे प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी दोनों स्क्वॉड में पर्याप्त मौके दिए गए हैं।

अफगानिस्तान वनडे टीम

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेट कीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल,दरविश रसूली, रहमत शाह, इकराम अलीखिल (विकेटकीपर),मोहम्मद नबी, अजमतुल्लाह उमरजई, राशिद खान, नांग्याल खारोताई, एएम गजनफर, जिया यू रहमान शरीफी, फरीद मलिक, बिलाल सामी।
रिजर्व खिलाड़ी:- कैस अहमद, सलीम सफी, बशीर अहमद।

अफगानिस्तान टेस्ट टीम

हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान),अब्दुल मलिक, सेदिकुल्लाह अटल, रहमत शाह, रहमानुल्लाह गुरबाज, रहमानुल्लाह जादरान, अफसर जजई (विकेटकीपर), इकराम अलीखिल (विकेटकीपर), अजमतुल्लाह उमरजई, शराफुद्दीन अशरफ, नांग्याल खारोताई, कैस अहमद, बिलाल सामी, जिया शरीफी, सलीम सफी।
रिजर्व खिलाड़ी:- बशीर अहमद, बहिर शाह, इस्मत आलम।

ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम ने मैत्री सीरीज के पहले मैच में भारत को 2-1 से हराया

नई दिल्ली,26 मई 2026। भारत और ऑस्ट्रेलियाई महिला हॉकी टीमों के बीच चार मैचों की मैत्री सीरीज मंगलवार को शुरू हुई। पर्थ के पर्थ हॉकी स्टेडियम में खेले गए पहले मुकाबले में भारतीय टीम को 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। भारत ने पहले क्वार्टर में पहला गोल किया। भारतीय टीम के लिए नवनीत कौर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिलाई। भारतीय डिफेंस पहले हाफ के समय मजबूत रहा। भारतीय टीम ने दूसरे क्वार्टर तक अपनी बढ़त बनाए रखी। दूसरे हाफ में मोमेंटम बदल गया जब ऑस्ट्रेलिया की एबी विल्सन ने दो पेनल्टी-कॉर्नर मौकों का फायदा उठाया और तीसरे और चौथे दोनों क्वार्टर में गोल करके मेजबान टीम को जीत दिलायी।

सीरीज का दूसरा मुकाबला बुधवार को खेला जाएगा। चार मैचों की मैत्री सीरीज भारतीय महिला हॉकी टीम की आने वाले एफआईएच हॉकी विमेंस नेशंस कप न्यूजीलैंड 2025-26 की तैयारियों में एक अहम मोड़ है। अपने तैयारी दौरे के चार मैचों में, सलीमा टेटे की कप्तानी वाली टीम का मकसद इस अहम विमेंस नेशंस कप इवेंट से पहले जरूरी मोमेंटम बनाना है।

भारत ने एसएएफएफ महिला चैंपियनशिप के पहले मैच में मालदीव को 11-0 से हराया

मार्गव ,26 मई 2026। टाइटल की दावेदार इंडिया ने ररुरु विमेंस फुटबॉल चैंपियनशिप में ज़बरदस्त शुरुआत की। यहां टूर्नामेंट के पहले मैच में मालदीव पर 11-0 की ज़बरदस्त जीत दर्ज करते हुए उन्होंने लगातार गोल किए। अवेका सिंह चार गोल और दो असिस्ट के साथ मैच की टॉप परफॉर्मर रहीं। 22 साल की इस मिडफील्डर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मालदीव के डिफेंस को तोड़ते हुए एक ज़बरदस्त प्रदर्शन किया, जिससे उनका पहला ग्रुप क्व मैच एकतरफ़ा हो गया।यह पहली बार भी था जब इंडियन विमेंस टीम फुटबॉल हब गोवा में खेली, और होम टीम ने शुरू से आखिर तक मैच पर हावी रहकर शानदार शुरुआत की। इसमें कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि अवेका को प्लेयर ऑफ़ द मैच का अवॉर्ड मिला, जब दुनिया में 69वें नंबर पर मौजूद इंडिया, जो 2019 में जीता अपना टाइटल वापस पाना चाहता था, ने अपने इरादे साफ़ कर दिए।

फूड सेफ्टी भवन में फर्जीवाड़े का स्वाद ?

डिग्री संदिग्ध, नियुक्ति पक्की, पदोन्नति एक्सप्रेस और नियम फाइलों में बेहोश पड़े रहे!

संदिग्ध डिग्री वालों का सुनहरा दौर! खाद एवं औषधि प्रशासन में नियम हुए बीमार

फूड सेफ्टी विभाग में फर्जी डिग्री का खेल...नौकरी भी मिली,प्रमोशन भी...

- डिग्री पर सवाल,फिर भी सरकारी माल! खाद विभाग में नियुक्ति और पदोन्नति का बड़ा खेल
- फर्जी योग्यता पर सरकारी कुर्सी? खाद एवं औषधि प्रशासन में उठे गंभीर सवाल
- नियम लाइन में खड़े रहे,जुगाड़ कुर्सी पर बैठ गया! '
- खाद्य विभाग में 'डिग्री सेफ्टी' फेल! संदिग्ध डिग्री से नौकरी और प्रमोशन का आरोप
- दवा जांचने वाला विभाग खुद जांच के घेरे में! नियुक्तियों पर उठे बड़े सवाल
- वरिष्ठों का हक छीन प्रमोशन एक्सप्रेस! खाद एवं औषधि प्रशासन में फाइलों का खेल '
- फूड सेफ्टी भवन में फर्जीवाड़े का स्वाद? नियुक्तियों से पदोन्नति तक सवाल ही सवाल
- सिस्टम की लैब में तैयार हुआ प्रमोशन फार्मूला! योग्यता नहीं,जुगाड़ बना असली दवा
- हाईकोर्ट के फैसलों के बाद भी संदिग्ध डिग्री वालों की नियुक्ति पर उठे सवाल
- स्थापना शाखा की भूमिका पर चर्चाएं तेज,वरिष्ठ कर्मचारियों में नाराजगी
- वैध अभ्यर्थी इंतजार करते रहे,विवादित डिग्री वाले अफसर बनते गए

न्यूज डेस्क

रायपुर,26 मई 2026 (घटती-घटना)। छत्तीसगढ़ का खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग इन दिनों किसी सरकारी नियामक संस्था से कम और किसी ऐसे प्रयोगशाला से ज्यादा दिखाई देने लगा है, जहाँ दवाइयों व खाद्य पदार्थ की नहीं बल्कि नियमों की 'टेस्टिंग' होती है,फर्क बस इतना है कि यहाँ नकली दवा पकड़ी जाए या न जाए,लेकिन कथित रूप से संदिग्ध डिग्री वाले अफसर आराम से सरकारी कुर्सी पर बैठ जाते हैं, फिर पदोन्नति भी पा लेते हैं,और वर्षों से सेवा कर रहे कर्मचारी देखते रह जाते हैं,अब विभाग के भीतर और बाहर एक ही सवाल गूंज रहा है क्या इस विभाग में सब कुछ फर्जी, जुगाड़ और संरक्षण के सहारे ही चलता है? मामले के केंद्र में दो नाम चर्चा में हैं सर्वेश कुमार और सिद्धार्थ पांडे,आरोप यह है कि वर्ष 2015 में हुई उनकी नियुक्ति ऐसी डिग्रियों के आधार पर हुई,जिनकी वैधता पर पहले से सवाल उठ चुके थे,लेकिन सरकारी व्यवस्था का कमाल देखिए जहाँ आम अभ्यर्थी का एक हस्ताक्षर गलत होने पर आवेदन निरस्त हो जाता है,वहीं यहाँ कथित तौर पर डिग्री की वैधता ही सवालों में रही और फिर भी नियुक्ति हो गई, और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई,कथित रूप से बाद में इन्हें पदोन्नति भी मिल गई, यानी सिस्टम ने सिर्फ नौकरी नहीं दी,बल्कि विशेष संरक्षण योजना भी लागू कर दी,उधर विभाग के कई वरिष्ठ कर्मचारी अपनी वरिष्ठता सूची लेकर ऐसे बैठे रह गए जैसे रेलवे स्टेशन पर बिना प्लेटफॉर्म के ट्रेन का इंतजार कर रहे हों।

जब हाईकोर्ट बोल चुका था, तब विभाग क्यों सोता रहा?

सूत्रों से मिले दस्तावेजों में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक महत्वपूर्ण फैसला मौजूद है,जिसमें डिस्टेंस एजुकेशन और राज्य के बाहर संचालित स्टडी सेंटरों से प्राप्त डिग्रियों की वैधता पर गंभीर टिप्पणी की गई थी,कोर्ट ने साफ कहा था कि विश्वविद्यालय बिना वैधानिक अनुमति राज्य की सीमाओं से बाहर अध्ययन केंद्र संचालित नहीं कर सकते,फैसले में यह भी उल्लेख है कि कई विश्वविद्यालयों की डिग्रियाँ नियमों के अनुरूप नहीं मानी जा सकतीं यदि वे निर्धारित अधिकार क्षेत्र के बाहर संचालित हों,अब बड़ा सवाल यह है कि जब ऐसे मामलों पर न्यायालय पहले ही स्पष्ट टिप्पणी कर चुका था,तब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नियुक्ति के समय दस्तावेजों की जांच किस आधार पर की? क्या दस्तावेज़ देखे ही नहीं गए? या देखे गए लेकिन 'देखकर भी अनदेखा' कर दिया गया? सरकारी भाषा में इसे प्रशासनिक प्रक्रिया कहा जाता है, पर जनता की भाषा में सेटिंग है।

फूड सेफ्टी विभाग में 'डिग्री सेफ्टी' गायब!

यह वही विभाग है जो बाजार में बिक रही दवाइयों व खाद्य पदार्थ की गुणवत्ता जांचता है,एक्सपायरी डेट,लाइसेंस,रासायनिक परीक्षण,सैंपलिंग सब कुछ बड़े नियम से होता है, लेकिन अब कर्मचारी व्यंग्य में पूछ रहे हैं दवाइयों व खाद्य पदार्थ की जांच करने वाले विभाग ने खुद अपने अधिकारियों की डिग्री की जांच की थी या नहीं? एक कर्मचारी ने तंज कसते हुए कहा यहाँ टैबलेट की सील टूट जाए तो जांच बैठ जाती है,लेकिन डिग्री की वैधता टूट जाए तो प्रमोशन मिल जाता है।

स्थापना शाखा-विभाग का असली 'पावर हाउस'?

इस पूरे मामले में सबसे ज्यादा चर्चा विभाग की स्थापना शाखा की हो रही है,आरोप यह है कि वर्षों से कुछ स्थायी चेहरे फाइलों की दिशा तय करते रहे। कौन पात्र है, कौन अपात्र, किसकी वरिष्ठता आगे बढ़ेगी,किसकी फाइल दबेगी सब कुछ कथित तौर पर 'विशेष प्रशासनिक प्रतिभा' से तय होता रहा,सरकारी दफ्तरों में अक्सर कहा जाता है मंत्री बदलते रहते हैं,लेकिन असली सरकार फाइल संभालने वाले लोग चलाते हैं,यही वजह है कि विभाग के भीतर अब यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि नियुक्ति और पदोन्नति की प्रक्रिया में नियमों से ज्यादा 'नेटवर्क' प्रभावी था।

वरिष्ठ कर्मचारी बने दर्शक, जूनियर बने अफसर

सरकारी सेवा में वरिष्ठता केवल अनुभव नहीं होती, वह कर्मचारी की वर्षों की मेहनत और प्रतीक्षा का परिणाम होती है,लेकिन आरोप है कि विवादित नियुक्तियों के बाद पदोन्नति में भी ऐसे लोगों को प्राथमिकता दी गई जिन्होंने कथित तौर पर नियमों की सीढ़ी नहीं बल्कि 'संपर्क की लिफ्ट' पकड़ी, इससे विभाग के कई कर्मचारियों में भारी नाराजगी बताई जा रही है,एक वरिष्ठ कर्मचारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा हमने वर्षों जंगल,गांव और फील्ड में काम किया, और कुछ लोग सीधे डिग्री लेकर आए,फिर कुर्सी और प्रमोशन भी ले गए।

राजपत्र में नियम,व्यवहार में रिश्ते?

पहले दस्तावेज़ में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की भर्ती और पात्रता संबंधी सूचनाएँ दर्ज हैं,कागजों में सब कुछ व्यवस्थित दिखाई देता है पात्रता,आरक्षण, योग्यता, चयन प्रक्रिया,लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तविक प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी थी? यही भारतीय नौकरशाही का सबसे बड़ा व्यंग्य है,फाइल में नियम ऐसे चमकते हैं जैसे नई किताब का कवर,लेकिन व्यवहार में वही नियम इतने कमजोर हो जाते हैं कि 'सिफारिश' का एक फोन आते ही दम तोड़ देते हैं।

क्या केवल दो लोग जिम्मेदार हैं?

यह पूरा मामला केवल दो अधिकारियों तक सीमित नहीं दिखाई देता,असली प्रश्न यह है कि यदि नियुक्ति गलत थी तो सत्यापन किसने किया? चयन समिति ने क्या जांचा? सेवा पुस्तिका किसने अनुमोदित की? पदोन्नति समिति ने वरिष्ठता और पात्रता का परीक्षण क्यों नहीं किया? यदि किसी की डिग्री विवादित थी तो जिम्मेदारी केवल नियुक्त व्यक्ति की नहीं बल्कि उस पूरे सिस्टम की बनती है जिसने उसे वैध घोषित किया।

विभाग में चर्चा है की यहाँ फाइल नहीं,कृपा चलती है...

खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग के भीतर इन दिनों कई पुराने मामलों की चर्चा फिर से शुरू हो गई है, कर्मचारी पुराने नियुक्ति आदेश, वरिष्ठता सूची और पदोन्नति रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं, एक अधिकारी ने व्यंग्य में कहा यह विभाग अब खाद्य एवं औषधि प्रशासन कम और 'कैरियर मैनेजमेंट एजेंसी' ज्यादा लगता है, दूसरे कर्मचारी ने हँसते हुए कहा यहाँ नियम वही लागू होता है, जिसके पीछे कोई बड़ा लागू कराने वाला हो।

फर्जीवाड़े का असर केवल विभाग तक सीमित नहीं...

यह मामला केवल प्रशासनिक अनियमितता नहीं है,इसका सीधा असर उन युवाओं पर पड़ता है जिन्होंने वैध विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी की और वर्षों मेहनत की, जब ऐसे मामलों में कथित रूप से नियमों को दरकिनार किया जाता है, तो पूरी भर्ती व्यवस्था पर अविश्वास पैदा होता है, युवाओं के मन में यह सवाल खड़ा होता है क्या मेहनत जरूरी है? या सिर्फ सही संपर्क?

अंतिम सवाल...

यदि डिग्रियाँ वैध थीं तो विभाग सार्वजनिक रूप से स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं करता? यदि सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ,तो वरिष्ठ कर्मचारियों की आपत्तियों का जवाब क्यों नहीं दिया गया? और यदि कहीं अनियमितता हुई, तो कार्रवाई किस पर होगी? सिर्फ नियुक्त व्यक्ति पर या उन अधिकारियों पर भी जिन्होंने वर्षों तक फाइलों पर 'सब ठीक है' लिखकर हस्ताक्षर किए?

सरकारी जांच-भारतीय प्रशासन का सबसे लंबा धारावाहिक

अब चर्चा है कि मामले की शिकायत उच्च स्तर तक पहुंच सकती है,यदि ऐसा हुआ तो संभव है कि विभागीय जांच समिति बने,लेकिन जनता को सरकारी जांच की गति अच्छी तरह पता है,पहले शिकायत आती है,फिर समिति बनती है,फिर फाइल घूमती है,फिर अधिकारी बदलते हैं,फिर रिकॉर्ड मांगे जाते हैं,फिर मामला 'विचाराधीन' हो जाता है,और अंत में सच उसी अलमारी में बंद हो जाता है जहाँ पुराने पंखे और टूटी कुर्सियाँ रखी रहती हैं।

सबसे बड़ा खतरा जनता का भरोसा टूटना

किसी भी नियामक विभाग की ताकत उसका अधिकार नहीं बल्कि उसकी विश्वसनीयता होती है,यदि जनता को यह लगने लगे कि जिस विभाग को कानून लागू करना है,वहीं नियमों का मजाक बन रहा है,तो पूरा सिस्टम अविश्वास के संकट में चला जाता है, और यही इस मामले का सबसे गंभीर पक्ष है।

अंत में...

छत्तीसगढ़ का खाद एवं औषधि प्रशासन विभाग आज एक ऐसे आईने के सामने खड़ा है जहाँ जनता पूछ रही है, जो विभाग नकली दवा पकड़ने का दावा करता है, क्या वह नकली योग्यता पहचानने में असफल रहा? या फिर पहचानकर भी चुप रहा? क्योंकि यह मामला केवल दो नियुक्तियों का नहीं है, यह उस व्यवस्था का चेहरा है जहाँ योग्यता लाइन में खड़ी रहती है और जुगाड़ सीधे कुर्सी पर बैठ जाता है।

गांजा और नशीले इंजेक्शन कारोबारियों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई,5 आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़,26 मई 2026। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी के मार्गदर्शन पर जिले में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन आघात' के तहत नशे के कारोबारियों के विरुद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में कल सीएसपी मयंक मिश्रा, डीएसपी उन्नति ठाकुर के नेतृत्व में साइबर थाना एवं कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा बीड़पारा क्षेत्र में अवैध गांजा बिक्री तथा रामलीला मैदान के पास नशीली बुट्रम इंजेक्शन बिक्री की सूचना पर त्वरित रेड कार्रवाई की गई। कार्रवाई में कुल 6.168 किलो गांजा, 24 नग नशीली बुट्रम इंजेक्शन, 7570 नगदी रकम एवं एक बाइक जब्त कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 25 मई 2026 को मुखबिर सूचना पर साइबर थाना एवं कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने बीड़पारा स्थित इरशाद खान के मकान में रेड कार्रवाई की। मौके पर आरोपी इरशाद खान पिता कुर्बान खान उम्र 37 वर्ष निवासी बीड़पारा रायगढ़ को पकड़ा गया। तलाशी के दौरान उसके कमरे में रखी प्लास्टिक बोरी से 06 पैकेट गांजा बरामद हुआ,जिसका कुल वजन 6.168 किलो पाया गया। आरोपी के कब्जे से एक सैमसंग मोबाइल भी जब्त किया गया। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसका साढ़ू जोगीडीपा निवासी मोहम्मद वसीम पिता बरकत मोहम्मद उम्र 43 वर्ष के साथ मिलकर गांजा बिक्री करता है। मोहम्मद वसीम ने दो दिन पहले उसके घर पर गांजा बिक्री के लिए छोड़ा था । सूचना पर पुलिस टीम ने जोगीडीपा पहुंचकर मोहम्मद वसीम को हिरासत में लिया, जिसने ओडिशा से गांजा लाना और बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी वसीम ने यह भी बताया कि उसका एक साथी उन्हें ओड़िशा से गांजा लाकर देता है । जिससे संपर्क करने पर उसी ने दो दिन पहले 6 पैकेट गांजा बिक्री के लिए दिया था।

साय कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले....

जीएडी के अधीन होगा कर्मचारी चयन मंडल

रायपुर,26 मई 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद ने राज्य के विभिन्न विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, मंडलों और स्थानीय निकायों में जमा स्क्रैप और अनुपयोगी सामग्रियों के पारदर्शी एवं व्यवस्थित निस्तारण के लिए भारत सरकार के उपक्रम मेटल स्क्रैप ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ सेलिंग एजेंसी अनुबंध की अवधि को आगामी तीन वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह अनुबंध नवंबर 2019 से प्रभावी है तथा 31 मई 2026 को समाप्त हो रहा था। MSTC के अत्याधुनिक ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से देशभर के खरीदार प्रतिस्पर्धी बोली लगाकर स्क्रैप सामग्री खरीद सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और राज्य को बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।

इस व्यवस्था से राज्य में स्क्रैप निस्तारण की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित, तकनीक आधारित और राजस्वोन्मुख हुई है। इस निर्णय से विभागों को अलग-अलग निविदा और विज्ञापन प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं होगी,प्रशासनिक समय और संसाधनों की बचत होगी,साथ ही कार्यालय परिसरों में स्वच्छता और स्थान प्रबंधन भी बेहतर होगा। मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल को सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके लिए 'छत्तीसगढ़ शासन कार्य (आवंटन) नियम' में संशोधन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 'छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, 2026' लागू होने के बाद पूर्व के छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल का विलय नए कर्मचारी चयन मण्डल में हो चुका है। साथ ही उसकी सभी परिसंपत्तियां एवं देनदारियां भी नए मण्डल में शामिल हो गई हैं। राज्य मंत्रिपरिषद ने सड़क निर्माण कार्यों में 01 अप्रैल 2026 के पश्चात बिटुमिन (डामर) की कीमतों में हुई असाधारण और अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए,राज्य के हित और निर्माण कार्यों में निरंतरता बनाए रखने के उद्देश्य से 01 अप्रैल 2026 से 30 जून 2026 की अवधि के लिए अनुबंधित ठेकेदारों को सीमित एवं आंशिक मूल्य राहत (क्षतिपूर्ति) प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह राहत केवल बिटुमिन मूल्य में हुई असाधारण वृद्धि के प्रभाव को कम करने हेतु निर्धारित फार्मूले के आधार पर दी जाएगी तथा अन्य निर्माण घटकों पर अनुबंध में पूर्व से प्रावधानित एस्केलेशन नियम यथावत लागू रहेंगे। वैश्विक परिस्थितियों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के कारण डामरीकरण कार्य प्रभावित होने लगे थे, जिससे सड़क निर्माण और संधारण कार्यों की गति बाधित होने की आशंका थी। भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा भी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं हेतु इसी प्रकार की राहत के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क निर्माण कार्य प्रभावित न हों और विकास कार्यों की गति बनी रहे, जिससे जनता को निर्धारित समय पर सड़क निर्माण कार्यों का लाभ मिल सके।

छत्तीसगढ़ में IAS,IPS और IFS अधिकारियों का महंगाई भत्ता 2% बढ़ा

रायपुर,26 मई 2026 । छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के महंगाई भत्ते में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का आधिकारिक आदेश जारी कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय (महानदी भवन) से जारी इस आदेश के बाद अब अधिकारियों का कुल महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो गया है। इस वृद्धि का लाभ अधिकारियों को 1 जनवरी, 2026 से नकद मिलेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, संभागीय आयुक्तों और कलेक्टर्स को जारी पत्र के अनुसार, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा 22 अप्रैल, 2026 को जारी ज्ञापन के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। अखिल भारतीय सेवायें (महंगाई भत्ता) नियम, 1972 के नियम-3 के तहत ये पुनरीक्षित दरें राज्य में कार्यरत अधिकारियों पर भी स्वतः लागू हो गई हैं।

छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का निधन

बिलासपुर,26 मई 2026। छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष रूपनारायण सिन्हा का कार्डियक अरेस्ट से निधन हो गया है। उन्हें साय सरकार में कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था। उनके निधन की खबर से भाजपा और राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। वे तिफरा में भाजपा के 2 दिवसीय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस प्रशिक्षण अभियान के प्रभारी की जिम्मेदारी भी उनके पास थी। कार्यक्रम के दौरान ही उनकी तबीयत बिगड़ी,

जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए बिलासपुर सिम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। रूपनारायण सिन्हा लंबे समय से भाजपा संगठन से जुड़े हुए थे। सामाजिक और योग गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। बिलासपुर के तिफरा में सोमवार को भाजपा जिला संगठन की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के दो दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ हुआ था। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री अरुण साव, सांसद रूपकुमारी चौधरी, विधायक अमर अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम का आज दूसरा दिन था। इस दौरान रूपनारायण सिन्हा की तबीयत बिगड़ी। फिलहाल, परिजन सिम्स से शव लेकर रायपुर रवाना हो गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने रूपनारायण सिन्हा के निधन को पार्टी के लिए अपूरणीय क्षति बताया है।

3उन्होंने कहा कि रूपनारायण सिन्हा ने भाजपा संगठन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर रहकर लंबे समय तक जिम्मेदारियां निभाई और पार्टी को मजबूत करने में अहम योगदान दिया।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफ्सेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)